

घाटती घाटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 38- सोमवार 08- दिसम्बर 2025, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये, www.ghatati-ghatana.com, RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने अहम भूमिका निभाई : राजनाथ

लेह, 07 दिसम्बर 2025। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन और केंद्र के बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी सड़कों, रियल टाइम कम्युनिकेशन, सेटलाइट स्पॉट, सर्वेलांस नेटवर्क व लाजिस्टिक स्पॉट से देश के सीमाओं पर आज हमारे सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने लद्दाख में दारबुक-शोक-दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनी 920 मीटर लंबी शोक टनल, गलवान मेमोरियल, कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों के 500



करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स सेना के बहादुर सैनिकों और बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के उन जवानों को श्रद्धांजलि हैं जो देश के लिए बिना थके काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के इतने सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कभी नहीं हुआ।

शोक टनल को बताया इंजीनियरिंग का कमाल...

रक्षा मंत्री ने कहा कि शोक टनल इंजीनियरिंग का कमाल है। इस ब्लाक में हर मौसम में भरोसेमंद कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, और यह टनल कड़ाके की सर्दियों के दौरान तेजी से तैनाती की क्षमता को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा... आज हम लद्दाख में दारबुक-शोक-दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनी 920 मीटर लंबी शोक टनल का उद्घाटन कर रहे हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक में बनी यह इंजीनियरिंग की अनोखी मिसाल, इस स्ट्रेटिजिक इलाके में हर मौसम में भरोसेमंद कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख के साथ-साथ आज जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी दूसरे प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए जा रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर में जितना जरूरी था उतना ही किया

पाकिस्तान को वेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ धैर्य का भी परिचय दिया। हमने उतना ही किया जितना जरूरी था। इतना बड़ा ऑपरेशन इस लिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी मजबूत है। सेनाओं ने कार्रवाई करने को सही समय पर अपनी साजो सामान पहुंचाया।

बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन 'कम्युनिकेशन' और 'कनेक्टिविटी' का दूसरा नाम बन गया

राजनाथ ने कहा... पिछले कुछ सालों में, जिस तेजी और कुशलता से बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन ने बॉर्डर इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उससे देश के विकास को भी काफी बढ़ावा मिला है। देशी समाधानों के जरिए, मुश्किल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करके बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन आज 'कम्युनिकेशन' और 'कनेक्टिविटी' का दूसरा नाम बन गया है।

इंडिगो संकट : एयरलाइन ने अबतक 610 करोड़ रिफंड किए

देशभर में यात्रियों को 3 हजार बेगैज भी लौटाए, 650+ फ्लाइट कैसिल

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर 2025। इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार को एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ का रिफंड कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने देशभर में यात्रियों के 3 हजार से ज्यादा बेगैज भी लौटाए हैं। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड या रि-बुकिंग पर एक्सट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सर्पोर्ट सेल बनाए गए हैं। इसके साथ ही इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी तेजी आई है। डोमेस्टिक फ्लाइट फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही है। इंडिगो के सीईओ ने पीटर एल्बर्स ने बताया कि आज हम 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 75% रहने का अनुमान है। ऑपरेट करती एयरलाइन रोजाना करीब 2300 उड़ानें ऑपरेट करती है। हमारी सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट कैसिल हुई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट कैसिल की थीं। रविवार को कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की 76 उड़ानें रद्द हुई हैं। इनमें 53



फ्लाइट उड़ान भरने वाली और 23 फ्लाइट लैंड होने वाली कैसिल हुई हैं।

विद्येतर्य बोले- अब तक एयरलाइन सेक्टर में दो कंपनियों का टकराव, अब तक कितना नियंत्रण जरूरी

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा- जब तक एयरलाइन सेक्टर में सिर्फ दो कंपनियां होंगी, तब तक हवाई किराया पर यह रोक जारी रहनी चाहिए। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा- मुझे खुशी है कि नागरिक उड़ान मंत्रालय ने अब जाकर इकोनॉमी क्लास के किराये को सीमित किया है। जब तक एयरलाइन सेक्टर में कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता, जनता की सेफ्टी के लिए कीमतों को सीमित करना ही उपाय है।

पश्चिम बंगाल में एक साथ 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ! भारत में तनातनी नहीं सनातनी चाहिए, तिरंगे में चांद नहीं चांद पर तिरंगा चाहिए : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

भारत में तनातनी नहीं सनातनी चाहिए, तिरंगे में चांद नहीं चांद पर तिरंगा चाहिए : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

कोलकाता, 07 दिसम्बर 2025। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार को आयोजित विशाल सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने पूरे संबोधन में सनातन धर्म की एकता, राष्ट्रीय गौरव और हिंदू समाज के जागरण पर जोर दिया। सनातन संस्कृति संसद द्वारा 'लोकखो कठे गीता पाठ' का आयोजन किए जाने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 'आज पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की पावन धरती कोलकाता में पांच लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। आस्था का उत्साह और सैलाब मंत्रालय ने अब जाकर इकोनॉमी क्लास के किराये को सीमित किया है। जब तक एयरलाइन सेक्टर में कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता, जनता की सेफ्टी के लिए कीमतों को सीमित करना ही उपाय है।



सनातन एकता इस देश और विश्व शांति का सबसे बड़ा साधन है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम 'गजवा-ए-हिंद' नहीं, 'भगवा-ए-हिंद' चाहते हैं। देखकर ऐसा लगा जैसे कोलकाता में महकूब मेला लगा हो। हम पश्चिम बंगाल और कोलकाता की जनता, भारत की जनता के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। हमें तिरंगे में चांद नहीं, चांद पर तिरंगा चाहिए और इसके लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। बेलदांगा में निलंबित विधायक हुमायूँ कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर कृष्ण मस्जिद की आधारशिला रखे जाने पर कहा कि अगर किसी की ऐसी आस्था है तो वह अपनी आस्था के अनुसार इसे स्वीकार कर सकता है। गीता का ज्ञान महान है, गीता

सकता है, इसमें कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे भगवान राम पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर हमारे मंदिर बनने पर कोई टिप्पणी करता है, तो अहंकार उजागर हो जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंची साव्त्री ऋतुभरा ने कहा कि अब समय आ गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाए। स्वामी ज्ञानानंद ने पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज से एक होकर यहां की नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया और कहा कि समाज को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा होना ही होगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपना कर्तव्य निभाओ और आज बंगाल अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है।

धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट गिरफ्तार

मुंबई, 07 दिसम्बर 2025। राजस्थान के एक आईबीएफ विशेषज्ञ से जुड़े 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट गंभीर कानूनी संकट में फंस गए हैं। उदयपुर में दर्ज एफआईआर के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें यारी रोड के गंगा भवन अपार्टमेंट में उनकी साली के घर से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला उन फिल्म और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स से संबंधित है, जिनके लिए करोड़ों रुपये लिए जाने का आरोप है, लेकिन आरोपकर्ता के अनुसार ये प्रोजेक्ट या तो पूरे नहीं हुए या उन्हें उचित श्रेय नहीं दिया गया। हालांकि, विक्रम भट्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह भ्रामक बताया है, खुद खारिज कर दिया है। उदयपुर के भूपालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इंडिरा आईबीएफ के संस्थापक डॉ. अनजय मुंडिया ने दावा किया कि उन्हें चार फिल्मों और कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स, जिनमें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित एक बायोपिक भी शामिल है, उनके लिए करीब 30 करोड़ रुपये निवेश करने को राजी किया गया। आरोप है कि इन फिल्मों से 200 करोड़ रुपये तक के मुनाफे का अनुमान बताकर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन धनादेश देने के बाद कुछ परियोजनाओं का काम रोक दिया गया जबकि पूरी हो चुकी परियोजनाओं में उन्हें वादानुसार श्रेय भी नहीं मिला।

भारत की सनातन आध्यात्मिक परंपरा की नींव ऋषि-मुनियों की तपस्या और ध्यान साधना पर आधारित : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर 2025। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रविवार को गुरुग्राम स्थित ब्रह्माकुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की सनातन आध्यात्मिक परंपरा की नींव ऋषि-मुनियों की तपस्या और ध्यान साधना पर आधारित है। उपराष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, राधा कृष्णन ने कहा कि 24 वर्ष पूर्व स्थापित यह केंद्र अब सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और यह गर्व की बात है कि ब्रह्माकुमारीज संस्था महिलाओं के नेतृत्व में देश के आध्यात्मिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक, चिकित्सक, प्रशासक और राजनेता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस केंद्र से जुड़कर ध्यान और शांति का संदेश ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजयोग और विषयना जैसी साधनाएं यह सिद्ध करती हैं कि वास्तविक शक्ति और स्पष्टता व्यक्ति के भीतर से आती है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प के तहत आंतरिक शांति, प्रसन्नता और संतुलन को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। राधाकृष्णन ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर की पर्यावरण संरक्षण पहलों की सराहना की और कहा कि यह केंद्र प्रधानमंत्री की मिशन लाइफ पहल के अनुरूप कार्य कर रहा है। उन्होंने 1 मेगावाट हार्डब्रिड सौर परियोजना, वर्षा जल संचयन, बायोगैस संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रीन किचन और वृक्षारोपण जैसे प्रयासों की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने नशामुक्त भारत, वरिष्ठ नागरिक सम्मान और कर्मयोग को बढ़ावा देने में ब्रह्माकुमारीज के योगदान की भी सराहना की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लखनऊ में शुरू किए गए 'राजयोग ध्यान' और 'विश्व एकता और विश्वास' अभियान का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि रजत जयंती वर्ष समाज और आध्यात्मिक जागरण के नए आयाम स्थापित करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पर्यावरण और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह सहित ब्रह्माकुमारीज संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।



सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस केंद्र से जुड़कर ध्यान और शांति का संदेश ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजयोग और विषयना जैसी साधनाएं यह सिद्ध करती हैं कि वास्तविक शक्ति और स्पष्टता व्यक्ति के भीतर से आती है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प के तहत आंतरिक शांति, प्रसन्नता और संतुलन को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा।

प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बल इंडा दिवस पर सेना के जवानों को किया नमन

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सशस्त्र बल इंडा दिवस के अवसर पर देश की तीनों सेनाओं के वीर जवानों की प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों का अनुशासन, संकल्प और अदम्य साहस देश को सुरक्षित रखने के साथ ही नागरिकों के मनोबल को भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कर्तव्यबोध और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने देशवासियों से सशस्त्र बल इंडा दिवस कोष में अधिक से अधिक योगदान देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सशस्त्र बल इंडा दिवस पर हम उन वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जो अटूट साहस के साथ देश की रक्षा करते हैं। उनका अनुशासन, संकल्प और अदम्य भावना हमारे देश और नागरिकों की सुरक्षा का कवच है। उनका समर्पण कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का सशक्त उदाहरण है। आइए, हम सभी सशस्त्र बल इंडा दिवस कोष में योगदान करें।



प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बल इंडा दिवस के अवसर पर देश की तीनों सेनाओं के वीर जवानों की प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों का अनुशासन, संकल्प और अदम्य साहस देश को सुरक्षित रखने के साथ ही नागरिकों के मनोबल को भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कर्तव्यबोध और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने देशवासियों से सशस्त्र बल इंडा दिवस कोष में अधिक से अधिक योगदान देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सशस्त्र बल इंडा दिवस पर हम उन वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जो अटूट साहस के साथ देश की रक्षा करते हैं। उनका अनुशासन, संकल्प और अदम्य भावना हमारे देश और नागरिकों की सुरक्षा का कवच है। उनका समर्पण कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का सशक्त उदाहरण है। आइए, हम सभी सशस्त्र बल इंडा दिवस कोष में योगदान करें।

एलओसी पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्चपैड सक्रिय

120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में, सुरक्षाबलों को मिट्टे, रेडिरेस्ट सीमा के करीब न पहुंचें

श्रीनगर, 07 दिसम्बर 2025। जम्मू-कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 68 लॉन्चपैड सक्रिय हैं। वहां 110 से 120 आतंकी जम्मू-कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दैनिक भास्कर को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक, अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि आतंकी सीमा के करीब भी न पहुंच सकें। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी लगातार एलओसी की ओर भेजा जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं।



एलओसी पर सुरक्षा बढ़ाई गई

सीमा से लगे गांवों और आगे की चौकियों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। फील्ड यूनिट्स को अधिक सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी काउंटर-इन्फिल्ट्रेशन ग्राइड को और मजबूत किया है। बॉर्डर पर अब नाइट विजन कैमरे, ड्रोन निगरानी, थर्मल सेंसर, ग्राउंड सेंसर, बड़ी हुई पेट्रोलिंग और अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है।

उज्जैन में महाकाल मंदिर की ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से होगी बंद

उज्जैन, 07 दिसम्बर 2025। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल 2026 के अवसर पर बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। मंदिर समिति ने घोषणा की है कि 25 दिसंबर से 05 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान भक्त केवल ऑफलाइन माध्यम से ही भस्म आरती और अन्य दर्शन की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए यदि इन तारीखों में दर्शन का कार्यक्रम बना रहे हैं, तो समय से पूर्व योजना बनाना आवश्यक होगा। मंदिर समिति के अनुसार, 31 दिसंबर से दो जनवरी के बीच करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। समिति का मानना है कि ऑफलाइन व्यवस्था के माध्यम से भीड़ पर बेहतर नियंत्रण रखा जा



सकेगा। वर्ष 2026 में महाकाल मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था भी बदल दी जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार भक्तों की एंटी त्रिवेणी संग्रहालय से होगी, वहां से महाकाल लोक के दर्शन करते हुए मान सरोवर तक पहुंचेंगे। इसके बाद टनल मार्ग से होत हुए गणेश मंडप में दर्शन करेंगे और अंत में एंजित टनल से बहड़ा गणेश मंदिर के सामने बाहर निकलेंगे। इस दौरान केवल ऑफलाइन पंजीकरण के आधार पर एंटी मिलेगी। श्रद्धालुओं को एक दिन पहले पहुंचकर फॉर्म भरना होगा।

ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो हम पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा जवाब देंगे, देश को सेना पर गर्व : नेवी चीफ

उज्जैन, 07 दिसम्बर 2025। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोका गया है, लेकिन ये अभी भी जारी है। भारत पर अगर कोई भी अटैक की कोशिश करेगा, तो हमारी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय दिया था। रविवार को दिल्ली में आर्म्ड फोर्स प्लेग डे फंक्शन 2025 में पहुंचे नेवी चीफ ने कहा-आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर केंद्र सरकार ने क्या कदम



उठाए थे। मुझे महसूस होता है कि इस देश के नागरिकों को अपनी सेना पर गर्व है। अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा, तो हम उसे करारा जवाब देंगे। इससे पहले 2 दिसंबर को भी नेवी चीफ ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मई 2025 में शुरू हुए इस

एम्पी में 2.36 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर, बालाघाट में हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे

बालाघाट, 07 दिसम्बर 2025। बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया। इसमें 62 लाख रुपये के इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल हैं। सभी 10 नक्सलियों पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें चार महिला और छह पुरुष नक्सली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट जिले में इस साल अब तक 10 हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास किया जाएगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा।



एम्पी में 2.36 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर, बालाघाट में हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे

संपादकीय

मनमानी की शर्मनाक कहानी
अक्षम हो गया डीजीसीए

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने डीजीसीए के नए नियमों का पालन न करके यात्रियों को बहुत परेशान किया। नियमों का उद्देश्य पायलटों को थकान से बचाना था, लेकिन इंडिगो ने लापरवाही बरती। उड़ानों के रद्द होने और देरी से चलने के कारण यात्रियों को समय और धन का नुकसान हुआ। इंडिगो को इसके लिए मुआवजा देना चाहिए। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने भारतीय यात्रियों को पिछले एक सप्ताह में जितना अधिक परेशान किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इंडिगो के यात्रियों को इसलिए परेशान होना पड़ा, क्योंकि उसने सुरक्षित विमान यात्रा के लिए नागरिक विमानों के संचालन की नियामक संस्था डीजीसीए के नए नियमों का पालन करने की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी।

ये नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत बनाए गए थे और सभी एयरलाइंस को उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पायलट एक निश्चित समय से अधिक ड्यूटी न करें। सुरक्षित विमान यात्रा के लिए यह आवश्यक होता है कि पायलट लंबी ड्यूटी के चलते थकान का शिकार न हों।

पायलटों को थकान से बचाने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए जहाँ एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयरलाइन ने पर्याप्त व्यवस्था की, वहीं इंडिगो ने ऐसा कुछ करना आवश्यक नहीं समझा और वह भी तब, जब नए नियम लागू करने की समयसीमा बड़ाई गई थी। इससे यही पता चलता है कि इंडिगो नए नियम लागू करने के लिए तैयार ही नहीं थी।

डीजीसीए को इसकी निगरानी करनी चाहिए थी कि इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस नए नियमों का पालन करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर रही हैं या नहीं? उसे इंडिगो पर इसलिए अधिक निगाह रखनी चाहिए थी, क्योंकि वह घरेलू विमान सेवा की सबसे बड़ी एयरलाइन है और उसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है। जहाँ डीजीसीए ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया, वहीं इंडिगो ने भी उसे यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं समझा कि वह नए नियमों का पालन करने की स्थिति में नहीं है या फिर उसे पायलट और अन्य कर्मचारी भर्ती करने के लिए कुछ और मोहलत दी जाए। चूंकि डीजीसीए ने सजगता नहीं बरती, इसलिए जब 1 दिसंबर से नए नियम लागू हुए तो इंडिगो की उड़ानें या तो रद्द होनी लगीं या फिर विलंब से चलने लगीं।

चूंकि रद्द और विलंब से चलने वाली उड़ानों की संख्या सैकड़ों में पहुंचने लगी, इसलिए परेशान होने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हवाई किराया भी बढ़ा होना लगा। हजारों विमान यात्री केवल समय पर अपने गंतव्य तक ही नहीं पहुंच सके, बल्कि उन्हें अतिरिक्त किराया भी देना पड़ा। इसका केवल आकलन ही नहीं किया जाना चाहिए कि डीजीसीए और इंडिगो की हिलाई के कारण लोगों के समय और धन की कितनी बर्बादी हुई, बल्कि उसका भुगतान भी किया जाना चाहिए।

इसके लिए किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि इंडिगो केवल खेद जताकर कर्तव्य की इतिश्री कर ले। यदि उसे यात्रियों के समय और धन की बर्बादी की भरपाई के लिए विवश नहीं किया गया तो उसका रवैया सुधरना कठिन ही है।

इंडिगो को किसी न किसी स्तर पर डंड का भागीदार इसलिए भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक तरह से जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा और साथ ही डीजीसीए को नए नियम लागू करने के अपने ऐसे फैसले को वापस लेना पड़ा, जो विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। डीजीसीए को इसका आभास होना चाहिए कि एक नियामक संस्था के रूप में उसकी क्षमता और साख पर गंभीर सवाल उठे हैं।

भारतीय विमानन बाजार इस समय विश्व का तीसरे नंबर का बड़ा बाजार है। विमान यात्री इंडिगो और एअर इंडिया पर ही अधिक निर्भर हैं। यह साफ दिखता कि इंडिगो ने डीजीसीए को दबाव में लेने की रणनीति पर काम किया और जानबूझकर जरूरत से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं। इसका कारण अपने मुनाफे की अधिक चिंता करना ही रहा होगा। निःसंदेह हर कंपनी को अपने मुनाफे की चिंता करने का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई कंपनी बाजार में अपने एकाधिकार वाली स्थिति का बेजा लाभ उठाकर नियामक संस्था के उन नियम-कानूनों का भी पालन न करे, जो लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

इंडिगो चाहती तो डीजीसीए के नए नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक पायलट और कर्मचारी आसानी से भर्ती कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने यह मान लिया कि डीजीसीए उस पर एक सीमा से अधिक दबाव नहीं डाल पाएगा। सच जो भी हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि डीजीसीए को नए नियमों पर अमल को दो माह के लिए टालना पड़ा है। इससे देश-दुनिया को यही संदेश जा जाएगा कि भारत सुरक्षित विमान संचालन के प्रति सतर्क नहीं।

इंडिगो के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह पहले भी यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान न रखने के जानी जाती रही है। इंडिगो से यात्रा करने वालों को यह शिकायत रहती है कि उसके संचालन दल के सदस्य उनसे रूखा व्यवहार करते हैं और वैसी कोई शिकायत नहीं देते, जैसी अन्य एयरलाइंस दे देती हैं। इन शिकायतों के बाद भी विमान यात्री इंडिगो से यात्रा करना इसलिए पसंद करते थे, क्योंकि उनका परिचालन समय पर होता था।

इसी के चलते एविएशन बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी बढ़ती गई, लेकिन यही बढ़ी हुई हिस्सेदारी अब एक समस्या के रूप में उभर आई। डीजीसीए कुछ भी दावा करे, इंडिगो ने नए नियमों को लागू करने के बजाय अपनी उड़ानों को स्थगित करके केवल लोगों को परेशान ही नहीं किया, बल्कि एक तरह से उसे झुकने के लिए भी बाध्य किया। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि कोई कंपनी बाजार में अपनी अधिक हिस्सेदारी के सहारे मनमानी करे और यहाँ तक कि नियामक संस्था को अपना एक जरूरी फैसला लागू करने में अक्षम कर दे। भले ही नागरिक उड्डयन मंत्री यह कह रहे हों कि सुरक्षा से समझौता किए बिना विमान संचालन संबंधी नए नियमों को स्थगित करने का फैसला किया गया है, लेकिन तथ्य तो यही है कि पायलटों को कम आराम के साथ विमानों का संचालन करना पड़ेगा। इंडिगो के रवैये के कारण जो संकेत खड़ा हुआ, उससे सरकार को सबक लेना होगा और यह देखा होगा कि नए विमान खरीद रही एयरलाइन को विमान संचालन की अनुमति तभी मिले, जब वे जरूरी नियमों का पालन करने में सक्षम दिखें।

ईमानदारी और निर्भयता से जीना क्या इतना कष्टप्रद हो रहा?



डॉ. प्रतिक भि. गेडम

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस विशेष

जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तब वह केवल अपना स्वार्थ साबित नहीं करता, बल्कि वह किसी अन्य का हक अनुचित तरीके से छिनता है, देश के विकास और सुव्यवस्था में अड़चने पैदा करता है, समाज में अपराध के बीज बोता है, साथ ही अन्याय करके पीड़ितों के सपनों को कुचलता है, जिसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, भ्रष्टाचार के कारण कई बार पूरे समाज को दशकों तक दुःख-दर्द झेलना पड़ता है। भ्रष्टाचार के कारण असंख्य मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, संघर्षमय जीवन का चक्र अतितीव्र होते जाता है।

सभी नागरिकों को विकसित होने का मौका मिलता है, समाज के हर वर्ग को मुख्य

धारा में लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहती है। कानून और सरकारी यंत्रणा इसके मजबूत स्तंभ हैं, जो हर पायदान पर नागरिकों के अधिकारों, सरकारी कार्यों एवं उपक्रमों का योग्य क्रियान्वयन कर विकास की नित नई कहानी लिखते हैं। अगर इस सुशासन में एक भी कड़ी अपनी जिम्मेदारी से पछाड़ कर खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करने लगे तो, संबंधित अनेक विभागों के लिए वह नासूर का काम करता है और धीरे-धीरे पूरे विभाग को खोखला कर देता है। ऐसा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी समाज, सरकार, देश और समस्त मानवजाती का दुश्मन होता है। बहुत बार खबरों में देश के कई मामूली सरकारी कर्मचारी, नेता धन कूड़े जैसे अरबों का धन छुपाये बैठे हैं, ऐसा पता चलता है। हमारा समाज और हम आधुनिकता का दम भरने वाले निकटू सोच वाली विचारधारा के लोग किस विश्वसनीयता के स्तर पर आ गए हैं?

मौलिकता, नैतिकता, सहजता, जागरूकता, नीतिमता, निस्वार्थता, परोपकारिता, संस्कारशीलता, ईमानदारी को छोड़ कर बुराई, कपट और स्वार्थ प्रवृत्ति को तेजी से अपना रहे हैं। लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि, अनुचित कार्य या अपराध होने पर भी लोग अपराधी का पक्ष लेने के लिए उत्तारू हो जाते हैं। कुछ दिन पूर्व मैं एक शख्स से मिला, उस शख्स ने पैसे को लेकर अपने विचार मुझसे साझा किये, उन्होंने कहा कि, पैसा ही भगवान है, पैसा ही सब कुछ है, चाहे वह किसी भी मार्ग से आये, पैसे से इज्जत, शोहरत, नाम होता है, हर चीज खरीद सकते हैं, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, तो हम क्यों ईमानदारी दिखाएँ? कोई नहीं पूछता कि पैसा किस मार्ग से



कमाया, पैसे के लिए अपराध करो, जेल जाओ, सजा भुगतो, लेकिन पैसा आने के बाद लोग आपके अपराध भी भूल जाते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है। लोगों की इतनी खराब सोच तो सीधे-सीधे देश में कानून व्यवस्था को झूठलाकर अपराधी करण को बढ़ावा देनेवाली है, ऐसे में तो हर और जंगलराज स्थापित होगा। आज देश में इस प्रकार के विचारधारा के लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। देश में हम कई बार देखते हैं कि चुनाव में संगीन गुनाहों के अपराधी उम्मीदवार को भी जनता चुनकर लाती है और दूसरी ओर उच्च शिक्षित निरपराध ईमानदार समाजसेवी उम्मीदवार की जमानत भी जग हो जाती है। हमारे आपसपास समस्याओं का आत्महत्या नहीं करते, इसके मुकाबले कोई भी अन्य पेशेवर व्यवसायी भी इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएँ नहीं करते। चाहे कितने ही घोटाले या आपराधिक गतिविधियों में नाम आ जाए फिर भी देश को चलाने वाले नेता लोग इतना तनाव भी नहीं लेते कि आत्महत्या करनी पड़े। ईमानदार व्यक्ति के हाथों अनजाने में छेटी सी भूल भी

ही सड़के सरकारी दारों की पोल खोल देती हैं। अरबों रुपये खर्च करके चलने वाली योजनाएँ कुछ समय में ही दम तो देती हैं, तब समायाबंधि में काम पुरे नहीं होते और उस कार्य का बजट बढ़ते जाता है। देश में आर्थिक विषमता की दूरी लगातार बढ़ ही रही है। अपने फायदे के लिए पार्टियां बदलने वाले राजनीतिक नेता दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। सरकार के एक भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी अनेक बार मासूमों की जान ले सकती है, भले ही मरने के बाद मृतक के परिवार को थोड़ी सी आर्थिक सहायता दी जाती हो, परंतु मृतक की जान तो लौटकर नहीं आती है। हमारे देश में जितने करियर किरान आत्महत्या करते हैं उतने किसी भी दूसरे देश में आत्महत्या नहीं करते, इसके मुकाबले कोई भी अन्य पेशेवर व्यवसायी भी इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएँ नहीं करते। चाहे कितने ही घोटाले या आपराधिक गतिविधियों में नाम आ जाए फिर भी देश को चलाने वाले नेता लोग इतना तनाव भी नहीं लेते कि आत्महत्या करनी पड़े। ईमानदार व्यक्ति के हाथों अनजाने में छेटी सी भूल भी

हो जाये तो बहुत पछतावा महसूस करते हैं, परंतु अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले भ्रष्ट लोग सुकून से जी कैसे लेते हैं? लोगों से नजरें मिलाकर स्वार्थमान से बात कैसे कर लेते हैं? परिवार, रिश्ते, अपनों के सामने आदर्श कैसे स्थापित करते हैं? क्या लोगों का जमीर मर चुका है? वस्तुएं, सेवाएं, रिश्ते-नाते में भी अब मिलावट नजर आता है, कब कौन धोखा दे जाये, कह नहीं सकते। आत्म सम्मान, ईमानदारी, ईमानदार, कर्तव्य परायणता, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता का कोई मोल नहीं बचा? लोगों को दुख देकर बदले में हम अपना सुख खरीद नहीं सकते। सुकून भरी नींद, स्वाभाविक खुशी, निःस्वार्थ प्रेम, मानसिक शांति और समाधानी मन से बढ़कर जीवन में कुछ अन्य की जरूरत नहीं है, यही असली आनंद है, जो हमें अपने आचरण द्वारा प्राप्त होता है। रोजाना अखबार और समाचार चैनलों पर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की खबरें रहती हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी भ्रष्टाचार का दर्श झेलते हुए आगे बढ़े हैं, भ्रष्टता सम्पूर्ण

व्यवस्था को खत्म करने की ताकत रखती है, अगर इसे सत्ता की ताकत मिल जाये तो उस देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। लोग जागरूक बनें, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझें। इंसान के रूप में जन्म लिया है तो ईंसानियत का फर्ज निभाएं। दूसरे का हक छीन कर नहीं बल्कि ईमानदार और परोपकारी की भूमिका निभानी चाहिए। जो व्यक्ति जितने ऊंचे जिम्मेदार पद पर कार्यरत होता है, वह जनता के लिए उतना ही ज्यादा जवाबदेही होता है, जनता उससे नहीं बल्कि उसने जनता से उटना चाहिए, अगर अनुचित कार्य करें तो। जनता अपने कर द्वारा सरकार को आर्थिक ताकत प्रदान करती है, जनता को अधिकार है कि वह जिम्मेदार अधिकारी या नेताओं को उतर मांगे। अपराधी और अनुचित कार्य करने वाले लोग डरकर रहना चाहिए ना कि सभ्य और ईमानदार लोग डर-डर कर जियें। भ्रष्टाचार करनेवाला व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के लिए लाभ मांगता है लेकिन लाभ देने वाला व्यक्ति भी अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अगर लाभ देना ही बंद कर दे तो लाभ मांगेगा किससे भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी हर नागरिक ने खुद से ही कानी होगी। अपने देश के लिए भले ही थोड़ी तकलीफ सहनी पड़े लेकिन देश का आनेवाला भविष्य बेहतर होगा, भावी पीढ़ी को उम्का हक मिलेगा। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी शाखाएँ जनता के मदद के लिए तत्पर हैं, उनकी मदद लें। हम उनसे ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। निश्चय न दें, न लेने दें, सतर्क रहें। राष्ट्रहित में सहयोग करें।

समय पर न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं

लंबित मामलों की बढ़ रही संख्या

यह स्वागतयोग्य तो है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है और उनकी पहली प्राथमिकता लंबित मामलों को निपटाने तथा मुकदमेबाजी की लागत को कम करने की है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक लंबे समय से एक के बाद एक न्यायाधीशों की ओर से ऐसा ही कूड़ कूड़ा जा रहा है और फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। आज की कटू सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वकीलों की महंगी फीस और तारीख पर तारीख के सिलसिले को देखते हुए आम आदमी के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का साहस जुटा सके। यदि वह किसी तरह ऐसा कर भी ले तो समय पर न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं।



दिलाया हो। यह सिलसिला दशकों से कायम है। हर नया मुख्य न्यायाधीश न्यायिक तंत्र में आमूल-चूल सुधार का वादा करता है, लेकिन अभी तक का अनुभव यही कहता है कि स्थितियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह है कि अब लोगों में निराशा घर करने लगी है। वे मुश्किल से ही अदालतों का दरवाजा खटखटाने हैं। यह समझा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में सुधार की बातें करने मात्र से ऐसा होने वाला नहीं है। न्यायपालिका के प्रति लोगों की आस्था ड्रिग, इसके पहले न्यायिक तंत्र में सुधार के

दोस कदम उठाने होंगे। ऐसा इसलिए भी करना होगा, क्योंकि किसी देश का विकास बहुत कुछ उसकी सुगम प्राथमिकता पर निर्भर करता है। जिस देश में समय पर न्याय नहीं मिलता, वहाँ केवल विवाद ही नहीं बढ़ते, बल्कि विकास के काम भी बाधित होते हैं और व्यवस्था के प्रति अस्तोष उपजाता है। इसके चलते नियम-कानूनों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समस्या केवल न्यायपालिका के स्तर पर ही नहीं, कार्यपालिका के स्तर पर भी है। आखिर वह एक तथ्य है कि सरकारें अपने ही लोगों से मुकदमेबाजी में उलझी हुई हैं। अच्छे हो कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएं। इसमें देरी स्वीकार्य नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

हरियाणा में टोल की मार

सबसे ऊँची तसल्ली, सबसे कम दूरी तयस्था पर टोल सवाल



डॉ. सत्यवान सोरभ, बड़वा भिवानी, हरियाणा

जब गुजरात जैसा बड़े आकार वाला प्रदेश पीछे रह जाए और छोटा हरियाणा टोल वसूली में सबसे आगे हो-तो यह महज

यह अंतर सिर्फ क्षेत्रफल का नहीं, बल्कि प्रशासनिक दूरदृष्टि, नीति-व्यवस्थापन और सार्वजनिक हित के मूल्यांकन का अंतर दिखता है। गुजरात में कुल 62 टोल प्लाजा हैं, वहीं हरियाणा में 75, तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि आखिर छोटे प्रदेश पर इतनी अधिक वसूली का बोझ क्यों? कौन-सी बाधाएँ या प्राथमिकताएँ हैं जिनके चलते हरियाणा में टोल प्लाजा की घनत्व अन्य राज्यों से कहीं अधिक है? टोल की संख्या अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या वहाँ बनती है जहाँ नियमों का पालन न हो, दूरी का



संयोग नहीं, नीतिगत असंतुलन का संकेत है लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में वह सच सामने आया जिसे हरियाणा के लोग वर्षों से महसूस कर रहे थे-टोल की बढ़ती बोझिल मार, अनियमित बाँचा, और हर कुछ किलोमीटर पर खड़े बैरियर। संसद में दिया गया यह सरकारी टोल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के कामकाज, प्राथमिकताओं और नीति-निर्माण की मानसिकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक टोल वसूली हरियाणा में होती है-917.1 प्रति नागरिक, जो पूरे भारत में नंबर एक है। यह तथ्य चौंकाता इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा का भौगोलिक आकार, सारसंख्या, मार्ग-लंबाई और औद्योगिक स्थिति गुजरात से कई स्तरों पर छोटी है। गुजरात हरियाणा से तीन गुना बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ टोल वसूली हरियाणा से कम है।

मानक तोड़ा जाए, और जनता की जेब से अधिकतम वसूली की कौशिल्य व्यवस्था के लक्ष्य के रूप में स्थापित हो जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया था कि जनता पर अनावश्यक भार न पड़े और सड़क-सुविधाओं का उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से हो। लेकिन हरियाणा का मामला बिल्कुल उलट है-यह देश का अकेला प्रदेश है जहाँ 2 टोल के बीच औसत दूरी 45 किलोमीटर है, यानी स्थापित मानक से 25 प्रतिशत कम। यह अंतर कोई छोटा सांख्यिकीय खेल नहीं, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक गड़बड़ी की ओर संकेत करता है। हरियाणा में सड़कों का जाल टूटा है, लेकिन हर सड़क पर दोलर की रणनीति क्या जनसुविधा के अनुरूप है?

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सतर्क खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

भगवान राम पर सियासत ठीक नहीं है...



संजय गोस्वामी, मुंबई

तृणमूल कांग्रेस के संसद में एन ए. ए. गुप्त ने 6 दिसंबर को जिस दिन 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा लेकिन भारी सुरक्षा के बीच बंगाल के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखी। ये राजनीति से प्रेरित है जिस पर सियासत करना ठीक नहीं है। ये एक सुनायोजित राजनीति चाल लगी क्योंकि इट और पाथर और लोगों का भारी संख्या में जुटाना कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित लगा इसपर खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सही नहीं माना है

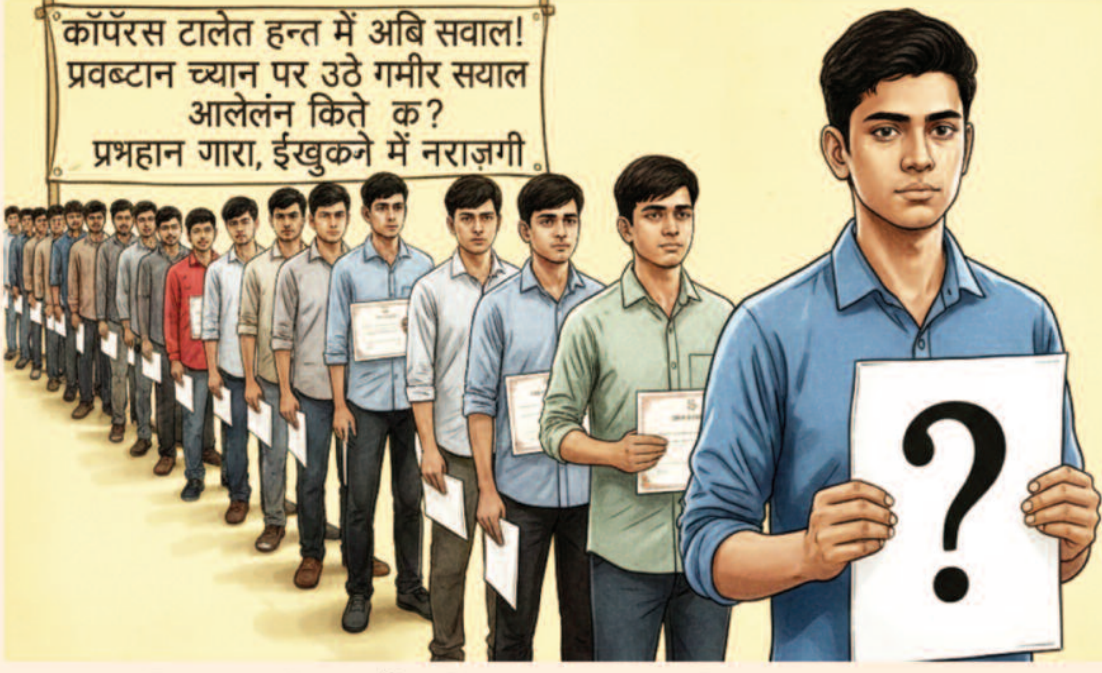
आखिर यदि राजनीति से प्रेरित नहीं है तो हुमायूँ कबीर को अचानक अब बंगाल चुनाव जो आने वाले हैं इस वक्त ही क्यों याद आया, इससे विदेशों में भारत की छवि लराब होती है आपस में इस मुद्दे पर लड़ना ठीक नहीं है और अब इस मुद्दे पर राजनीति करना बिलकुल व्यर्थ है क्योंकि जो हुआ उसके बाद उसके लिए उग्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे और उस समय काफी दंगा भी हुए पहली बात तो ये है भगवान राम ने कभी धर्म, जाति, पाती के लिए नहीं मर्यादा के लिए जाने और पूजे जाते हैं जो सभी धर्म में मानवता का सम्मान करता है केवल मंदिर में राम हैं ऐसा नहीं है वो सबके है वो एक विचार है जिसे पहले हिन्दू, मुस्लिम दोनों ने पूजा है जैसे कबीर दास, रहीम और भी कई सूफि संत व पीर थे रहीम ने हिन्दू-संस्कृति को ये भलीभाँति परिचित है। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। कुल मिलाकर इनकी म्यारह रचनाएँ प्रसिद्ध हैं।



इनके प्रायः 300 दोहावली नाम से संगृहीत हैं। दोहों में ही रचित इनकी एक स्वतन्त्र कृति नगर शोभा है। इसमें 142 दोहे हैं। इसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का श्रृंगारिक वर्णन है। अतः भगवान राम एक विचार है जो हमें कठिन परिस्थिति में लड़ने की प्रेरणा देता है और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना अतः अब इसपर सियासत करना ठीक नहीं है अतः इसपर

शान्ति से काम लेना चाहिए और हमेशा गरीबों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए जो भगवान राम को सियासत में घसीट रहे हैं है आखिर कब तक इस पर राजनीति कर सता में बने रहेंगे क्योंकि हमें एक दिन दुनिया से जाना भी है राम नाम की एक अलग महिमा है जो सर्वत्र है महिमा का अर्थ है होता है महानता, पराक्रम, प्रताप, गौरव, प्रसिद्धि, गरिमा आदि जो भगवान राम के नाम में व्याप्त है

को कम करती है। टेलोमीयर (गुणसूत्रों के अंत में सुरक्षात्मक कैप) की लंबाई सीधे दीर्घायु से जुड़ी है। संदेश: मर्यादा का अन्वयास व्यक्ति को तनाव-प्रेरित त्वरित एजेंज से बचाता है, जिससे टेलोमीयर कोशिका का संरक्षण होता है। [सत्य परायणता आंतरिक सामंजस्य सत्य परायण होने का अर्थ है मन, वचन और कर्म की एकता। हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य जब कोई व्यक्ति के साथ जीता है, तो उसके भीतर कोई द्वंद नहीं होता। योग और ध्यान में, हृदय और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य को उच्च चेतना और उत्कृष्ट स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। असत्य या द्वंद इस सामंजस्य को तोड़ते हैं। एंडोर्फिन और डोपामाइन सत्पुरुष बनने का प्रयास पुरस्कार प्रणाली को सक्रिय करता है, जिससे सकारात्मक न्यूरोट्रॉपिक (जैसे डोपामाइन और एंडोर्फिन) स्रावित होते हैं। ये मनोदशा को बेहतर बनाते हैं और एजेंज प्रक्रिया को धीमा करते हैं।



कांग्रेस के टैलेंट हंट में अजीब सवाल... प्रवक्ता चयन पर उठे गंभीर सवाल

प्रवक्ता बनने पहुंचे इक्षुक और चयन समिति के सामने खड़े हुए 'प्रश्नों' के प्रश्न

- **विटो पावर, पूर्व जिलाध्यक्ष की मौजूदगी और विचित्र इंटरव्यू, क्या चयन पहले से तय ?**
- **आंदोलन कितने किए ? प्रवक्ता चयन में पूछा गया अजीब सवाल, इक्षुकों में नाराजगी**
- **पूर्व जिलाध्यक्ष चयन समिति में पक्षपात और पूर्व-निर्धारित परिणाम की आशंका**
- **ऑनलाइन आवेदन, शॉर्टलिस्ट और फिर जिलाध्यक्षों का विटो पावर प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न**

-न्यूज डेस्क-

अम्बिकापुर 07 दिसम्बर नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा सरगुजा संभाग के सभी जिलों के लिए प्रवक्ताओं के चयन हेतु आयोजित टैलेंट हंट कार्यक्रम अब सवालों के घेरे में है, राजीव भवन अम्बिकापुर में हुए इस साक्षात्कार में उन उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिन्होंने 21 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन चयन प्रक्रिया और पूछे गए सवालों को लेकर इक्षुकों में असंतोष दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का यह टैलेंट टेस्ट एक अवसर था अपने भीतर पारदर्शिता दिखाने का, युवाओं को भरोसा दिलाने का, और योग्यता आधारित चयन का संदेश देने का, लेकिन यदि यह प्रक्रिया भी पहले से तय समीकरणों का विस्तार बनकर रह गई, तो पार्टी जिस बदलाव की बात करती है, वह सिर्फ मंचों की घोषणा बनकर रह जाएगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे जिसकी अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 थी और उन्हीं आवेदनों में से साक्षात्कार के लिए इक्षुक लोगों को बुलाया गया था, इसके अतिरिक्त जिला अध्यक्ष कांग्रेस को अलग से विटो पावर प्रदान किया गया था, जिसके अनुसार ऑनलाइन आवेदनों के अतिरिक्त वह दो अपने पसंद के लोगों को भी साक्षात्कार में शामिल करा सकते थे, जिन्हें ऑनलाइन आवेदनों की शॉर्ट लिस्ट तैयार होने के बाद भी साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिल सकता था, सरगुजा संभाग के सभी जिलों के लिए राजीव भवन अम्बिकापुर में हुए साक्षात्कार में इक्षुक लोगों ने साक्षात्कार दिया और अब उनमें से किसे किस जिले की जिम्मेदारी मिलेगी यह चयन समिति

प्रवक्ता इंटरव्यू या आंदोलन की गिनती? सवालों पर सवाल

साक्षात्कार से होकर आए एक उम्मीदवार ने बताया कि उनसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका प्रवक्ता की भूमिका से कोई सीधा संबंध नहीं था, उदाहरण: आपने अब तक कितने आंदोलन किए? इक्षुकों का कहना है कि जहाँ प्रवक्ता की भूमिका राजनीतिक समझ, टीवी डिबेट कौशल, विपक्षी प्रवक्ताओं को तर्कों से जवाब देने की क्षमता, विचारधारा और मुद्दों पर पकड़ से आंकी जानी चाहिए थी, वहाँ आंदोलन की संख्या पूछना टैलेंट हंट की मूल भावना से मेल नहीं खाता।

चयन समिति में पूर्व जिला अध्यक्ष की मौजूदगी भी चर्चा में...

साक्षात्कार में एक पूर्व जिलाध्यक्ष के शामिल होने पर भी सवाल उठ रहे हैं, इक्षुकों के अनुसार, जब चयन निष्पक्ष होना चाहिए, तब किसी पूर्व पदाधिकारी की भूमिका चयन में दखल जैसी लगती है।

जिलाध्यक्षों को मिला 'विटो पावर'... प्रक्रिया पर और भी गंभीर सवाल

सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को विशेष अधिकार दिया था कि ऑनलाइन आवेदन और शॉर्टलिस्ट तैयार होने के बाद भी वे अपने दो पसंदीदा लोगों को सीधे साक्षात्कार में भेज सकते थे, यानी प्रक्रिया के बाहर के नाम भी चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे, इक्षुकों का कहना है कि यह प्रावधान चयन के निष्पक्ष होने पर संदेह पैदा करता है।

तय करेगी, वैसे कांग्रेस में सभी तरह के चयन को लेकर एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है लेकिन जब प्रक्रिया का परिणाम सामने आता है यह बात सामने नजर आती है कि प्रक्रिया दिखावा मात्र था और जो परिणाम है वह पहले से तय था, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी देखने को मिला कि कई जिलों में जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कोई समर्थन प्रक्रिया के दौरान नहीं मिली उन्हें ही जिले की पार्टी की पार्टी कमजोर मिली, अब प्रवक्ताओं की नियुक्ति में भी यदि ऐसा ही कुछ सामने आता है जो वह अचरज का विषय नहीं होगा क्योंकि यह अब कांग्रेस की पहचान जैसा मामला बन चुका है, जहाँ समर्थन और योग्यता की बजाए बड़े नेताओं की सहमति मान्य रखती है।

प्रक्रिया हर बार चलती है, पर परिणाम अक्सर पहले से तय... कार्यकर्ताओं का आरोप...

कांग्रेस में चयन प्रक्रियाओं को लेकर यह चर्चा नहीं है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिलाध्यक्ष चयन हो या समानतामक नियुक्तियों या अब प्रवक्ता चयन प्रक्रिया औपचारिक रहती है, लेकिन परिणाम पहले से तय होते दिखते हैं, कुछ जिलों में हाल ही में ऐसे जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, जिन्हें प्रक्रिया के दौरान बहुत कम समर्थन मिला था, फिर भी वे अंतिम चयन में आगे निकल आए, इसी पैटर्न को देखते हुए इक्षुकों का कहना है यदि प्रवक्ता चयन में भी यही दोहराया गया तो यह अचरज की बात नहीं होगी, कांग्रेस में अब योग्यता नहीं, सहमति (बड़े नेताओं की) अधिक मान्य रखने लगी है।

दैनिक घटती-घटना का एडिटरियल कॉलम में अपना विचार

कांग्रेस का यह टैलेंट हंट एक अवसर बन सकता था योग्य वक्ताओं को सामने लाने का, लेकिन जब इंटरव्यू की दिशा आंदोलन की गिनती में बदल जाए, जब चयन समिति के स्वरूप पर ही संदेह उठने लगे, और जिलाध्यक्षों को विटो पावर देकर प्रक्रिया को लचीला बना दिया जाए, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रवक्ता पद वास्तव में 'प्रक्रिया' से तय होगा या 'पसंद' से? कांग्रेस को यदि अपने संचार तंत्र को मजबूत करना है, तो उसे चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, तर्क-आधारित और योग्यता-केंद्रित बनाना होगा, वरना प्रवक्ता नहीं, 'प्रबंधित नाम' सामने आएंगे और पार्टी का नुकसान भी उन्हीं बहसों में दिखेगा जहाँ प्रवक्ता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



प्रक्रिया बनाम प्रभाव... कांग्रेस का टैलेंट टेस्ट

कांग्रेस पार्टी ने सरगुजा संभाग में प्रवक्ता चयन के लिए टैलेंट हंट का आयोजन कर यह संदेश देने की कोशिश की कि संगठन अब योग्यता आधारित ढांचे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कार्यक्रम से बाहर निकलते ही प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएँ बताती हैं कि इस प्रक्रिया ने जितनी उम्मीदें जगाई थी, उतनी ही सवाल भी खड़े किए हैं, एक प्रवक्ता का चयन महज साक्षात्कार का विषय नहीं होता यह पार्टी की वैचारिक आवाज, तर्क क्षमता, जनसंवाद और मीडिया प्रबंधन का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए चयन प्रक्रिया जितनी मजबूत और पारदर्शी होगी, पार्टी का प्रदर्शन उतना ही प्रभावी दिखाई देगा, लेकिन अम्बिकापुर में पूछे गए प्रश्नों और चयन समिति की संरचना को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस संगठन अभी भी पुराने ढर्रे पर अटका हुआ है, जहाँ योग्यता से ज्यादा रिश्ते और समीकरण भारी पड़ते हैं, सबसे बड़ा सवाल चयन समिति को लेकर है। जब समिति में पूर्व जिला अध्यक्ष जैसे पदाधिकारी मौजूद हों, तो स्वाभाविक है कि निष्पक्षता पर प्रश्न उठेंगे। साथ ही जिलाध्यक्षों को दी गई 'विटो पावर' ने मॉरटे-आधारित चयन को कमजोर किया है। यदि किसी के पास इतनी छूट ही कि शॉर्टलिस्ट के बाहर भी वह अपने पसंद के दो लोगों को जोड़ सके, तो तोग प्रक्रिया की नीयत पर सवाल उठाने से खुद को रोक भी नहीं पाएंगे, चयन में पूछे गए सवालों पर भी असहमति है, प्रवक्ता के काम की प्रकृति के अनुसार उसकी तर्कशक्ति, राजनीतिक समझ, और मीडिया में खुद को स्थापित करने की क्षमता प्रमुख होनी चाहिए। लेकिन यदि उससे पूछा जाए कि उनसे कितने आंदोलन किए, तो यह चयन की गंभीरता को हल्का कर देता है, आंदोलन संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर प्रवक्ता चयन का आधार नहीं, कांग्रेस अवसर कतली है कि वह युवाओं को अवसर देती है, प्रक्रिया को महत्व देती है और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानती है। लेकिन जब प्रक्रियाएँ 'कागज पर पारदर्शी' और 'भूगोल में प्रभावित' दिखने लगें, तो पार्टी की विश्वसनीयता सवालों में घिरती है, आज कांग्रेस को एक बात समझनी होगी प्रक्रिया के प्रति विश्वास, परिणामों को विवादित बना देता है, और जब प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पद का चयन विवाद से घिर जाए, तो उसका असर केवल संगठन पर नहीं, पार्टी की सार्वजनिक छवि पर भी पड़ता है।

नशे की हालत में वाहन चलने वाले ई-रिक्शा चालक पर साढ़े 10 हजार का जुर्माना

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

यातायात पुलिस द्वारा 6 दिनों के चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ई-रिक्शा सजीजी 15 ईजी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। जांच के बाद जब चालक मनीष यादव, निवासी-यादव आटा चक्की, अम्बिकापुर से वाहन के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वह कोई भी दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहा। प्रकरण को गंभीर मानते हुए पुलिस ने चालक को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ



न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने और आवश्यक दस्तावेज

नहीं रखने के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 एवं 130(3) के तहत चालानी कार्रवाई की। न्यायालय द्वारा चालक पर कुल 10 हजार 500 रुपये समन शुल्क लगाया गया, जिसे मौके पर वसूल किया गया। घटना के बाद सरगुजा पुलिस ने सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे शराब पीकर किसी भी स्थिति में वाहन न चलाएँ। साथ ही, वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज और अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखें। पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रदर्शनी के माध्यम से बताई गई नए आपराधिक कानून की जानकारी

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता पर आधारित पुलिस विभाग की प्रदर्शनी का वरिष्ठ अधिकारियों ने 6 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर में अवलोकन किया। सरगुजा पुलिस द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण आपराधिक प्रकरणों, उनसे जुड़ी धाराओं तथा उनकी सक्षम व्याख्याओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि यह आम जनता में अपराध जागरूकता बढ़ाने और नए कानून की

बारीकियों को समझाने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जनता और कानून के बीच की प्रक्रिया को सरल रूप में समझाने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी उपयोगी साबित होगी। प्रदर्शनी एक माह तक लगातार आम लोगों के लिए खुली रहेगी, जिससे अधिक से अधिक नागरिक नए प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमोलक सिंह हिल्लो के निदेशन में थाना प्रभारी मणिपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह तथा सहायक उपनिरीक्षक संदीप सिंह उपस्थित रहे।



ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का हुआ आयोजन सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों की दी गई जानकारी

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

क्लेक्टर विलास भोसकर एवं जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन मनरेगा कार्यस्थल तथा गांव पंचायत भवनों में किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को आजीविका डबरी बनवाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभी को



जन मनरेगा एप एवं ग्राम पंचायत में चस्पा कोड का स्कैन कर जानकारी प्राप्त करने के बारे में बताया गया। वहीं भूजल संरक्षण से गांव में पानी की समस्या को दूर करने हेतु जल संचयन के कार्यों में अधिकता लाने हेतु कार्य योजना के संबंध में भी चर्चा की गई।

आत्मनिर्भर भारत और SIR 2025 : युवा शक्ति का शंखनाद!

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

अम्बिकापुर के राजमोहनी देवी भवन में आज युवा मोर्चा का विशाल विधानसभा स्तरीय युवा सम्मेलन पूरे उत्साह, ऊर्जा और गरिमा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह हिंसोदिया के उद्बोधन ने युवाओं में नवसंकल्प और जोश का संचार किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और SIR 2025 के संकल्प को युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में हरपाल सिंह भाग्य, अश्विनेश केशरी, विनोद हर्ष, अरुणा सिंह,



राजकुमार बंसल, जयेंद्र मिश्रा, निलेश सिंह, गोल्डी बिहाडे सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष ऊर्जा प्रदान की। शहर के युवा उद्यमी अभिषेक सिंह और आयुष तिवारी ने आत्मनिर्भर भारत पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए युवाओं को विभिन्न रोजगार सृजन के अवसरों के लिए प्रेरित किया। दोनों ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप सहायता,

93 नग नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

संभागीय आवकारी उड़नदस्ता टीम ने सूरजपुर जिले से एक नशीले इंजेक्शन सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आवकारी विभाग ने 93 नग इंजेक्शन के साथ आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को संभागीय आवकारी उड़नदस्ता टीम को सूरजपुर जिले के रामानुजगढ़ क्षेत्र में गश्त में थी। तभी मुखबिर से जानकारी मिली पंडरीपानी निवासी खलेश्वर राम साहू अपने घर में भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन रखकर बिज्जी कर रहा है। सूचना पर सहायक जिला आवकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने तत्काल अपनी टीम के साथ उसके घर में दबिश दी। टीम को देखते ही खलेश्वर साहू अपने बाड़ी की ओर झोला लेकर भागने लगा। जिसे टीम ने दौड़कर उसे पकड़ा और झोले की तलाशी ली, झोले में 37 नग रेक्सोजेसिक व 56 नग एक्विल इंजेक्शन पाया गया। जिसे टीम ने जल्द कर आरोपी खलेश्वर साहू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 सी के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।



संभागीय आवकारी उड़नदस्ता टीम ने सूरजपुर जिले से एक नशीले इंजेक्शन सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आवकारी विभाग ने 93 नग इंजेक्शन के साथ आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है।

क्या उप पंजीयक भी दे रहे हैं संरक्षण? स्थानांतरण आदेश ठंडे बस्ते में, समितियों में जुगाड़ राज जारी

क्या धान खरीदी समितियों का स्थानांतरण सिर्फ कागजी खानापूर्ति?

22 नवंबर के आदेश पर सबसे बड़ा सवाल...कौन जॉइन करेगा, कौन जुगाड़ से बच जाएगा?

-शमरोज खान-

सूरजपुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

रसुखदार-जात-विदीत के चंगूल में नया उप पंजीयक? 24 नवंबर की समयसीमा बीत गई...पर कार्यभार किसने लिया? 22 नवंबर के तबादले सिर्फ कागजों में ही है जिला प्रशासन का चिर-परिचित खेल 'जिसका जुगाड़ मजबूत, वही पदस्थ है, धान खरीदी समितियों में 'पोस्ट होल्डिंग सिडिकेट' स्थानांतरण के बावजूद प्रबंधक पुरानी कुर्सी नहीं छोड़ रहे अफसरों का अनौपचारिक संरक्षण या राजनीतिक शह? जिले में घूम रहा बड़ा सवाल 'आखिर किसका बचाव हो रहा है? कागज पर तबादला जमीन पर मनमानी नई जगह कौन जॉइन करेगा और कौन जमा रहेगा? अधिकारियों में संशय, बत्ता दें की 22 नवंबर को जारी आदेश में जिले की कई धान खरीदी समितियों के सहायक समिति प्रबंधकों का स्थानांतरण किया गया है। किसे कहा भेजा गया, किसे कौन-सी नई जिम्मेदारी दी गई...सब कुछ कागज पर साफ दर्ज है, लेकिन असली सवाल आदेश में नहीं, जमीनी हकीकत में छिपा है।

स्थानांतरण का आदेश... या मतेले की मौत?
22 नवंबर को जारी आदेश में स्पष्ट था सभी सहायक समिति प्रबंधक 24 नवंबर तक नई जगह कार्यभार ग्रहण



करें और इसकी सूचना दें, लेकिन 25 नवंबर की सुबह होते-होते जमीनी हकीकत वही पुरानी थी, कई प्रबंधक अभी भी पुरानी जगह से ही पूरी व्यवस्था चलाते हुए, नई जगह कार्यभार ग्रहण करने की बजाय टालमटोल और सबसे बड़ा सवाल क्या यह सब 'उप पंजीयक-नेता-समिति प्रबंधक' त्रिकोण के समन्वय से हो रहा है? जिले में चर्चाएं तेज हैं जुगाड़ मजबूत तो आदेश कागज में...जुगाड़ कमजोर तो अधिकारी नई जगह

पहुंच जाता है, यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील सीजन में किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला है। जब प्रबंधक ही बदल लिए नहीं जाते, तो खरीदी में पारदर्शिता कैसे आएगी? अवैध वसूली, टोकन गड़बड़ी, रकबा कटौती जैसी शिकायतें कब खत्म होंगी? स्थानांतरण कानून नहीं प्रक्रिया है, और जब प्रक्रिया ही रसुख के पैरों तले दब जाए, तो धान खरीदी की

स्थानांतरण तो हो गया...लेकिन क्या नए पदस्थापना स्थल पर पहुँचेंगे भी?

कागज का तबादला... या जमीन पर भी बदलाव?



जिले का रिपोर्ट बताता है की आदेश निकल जाता है, पर अधिकारी रिपोर्टिंग नहीं करते, पुराने पदस्थ लोग स्थानीय लाभ-व्यापार-प्रबंधन-राजनीति के गडजोड़ में इतने गहरे होते हैं कि वहाँ टिके रहना उन्हें ज्यादा सुट करता है, यानी आदेश ऊपर से आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर चलता है वही अधिकारी, जिसका 'जुगाड़' मजबूत हो।

24 नवंबर की समयसीमा बीत गई, किसने कार्यभार लिया?

आदेश में स्पष्ट था कि सभी प्रबंधक 24.11.2025 तक नई जगह कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन जिला प्रशासन का इतिहास कहता है 'जुगाड़ मजबूत तो आदेश कागजों में, जुगाड़ कमजोर तो अधिकारी नई जगह, अब जिले में यही चर्चा, कौन नई जगह जॉइन करेगा? कौन पुरानी जगह ही नेताओं-अधिकारियों से 'अनौपचारिक संरक्षण' लेकर जमा रहेगा?

स्टेटमेंट लेने गए...पर स्टेट नहीं मिलता

इस मामले में विभागीय 'स्टेट' लेने की कोशिश की गई, पर कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं मिली।

सबसे बड़ा सवाल क्या यह तबादला सब में लागू होगा?

सूत्रों के अनुसार धान खरीदी जैसे संवेदनशील सिस्टम में, जहाँ करोड़ों का लेन-देन और स्थानीय दबाव बराबर चलता है, क्या यह स्थानांतरण जमीनी रूप से लागू हो पाएगा, या यह आदेश भी सिर्फ कागजी में दर्ज होकर रह जाएगा?

सूरजपुर में बड़ी कार्रवाई! 21 मवेशियों से ढ़ंसा ट्रक हुआ राजसात, तीन तस्कट जेल भेजे गए

-संवाददाता-

सूरजपुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

अवैध पशु परिवहन और पशु क्रूरता पर अंकुश लगाने प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जन्त किए गए स्वराज माजदा ट्रक क्रमांक P 64 BT 1334 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस. जयवर्धन ने शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। दिनांक 11 जून 2025 को लोडिंग चौक के पास यह ट्रक क्षमता से अधिक पशुओं से भरा हुआ पकड़ा गया था। वाहन में 16 भैंस, 4 भैंसा और 1 पड़िया-कुल 21 मवेशियों को ढ़ंसाकर क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। पूछताछ में वाहन मालिक मो. रहीम (28 वर्ष) निवासी



जियावन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ पशुओं को अवैध रूप से कानपुर ले जा रहा था। चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में इस मामले में अपराध क्रमांक 285/2025 दर्ज किया गया था, जिसमें पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(घ) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी मो. रहीम, तनवीर अहमद (34 वर्ष) एवं खालिद हुसैन (21 वर्ष) को

जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यव्यापी महापरीक्षा का सफल आयोजन केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर सहित 466 परीक्षा केन्द्रों में उत्साहपूर्वक शामिल हुए 15 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों नवसाक्षर...



-संवाददाता- अम्बिकापुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, रायपुर के निर्देशानुसार आज रविवार को सरगुजा जिले में राज्यव्यापी महापरीक्षा अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह परीक्षा कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान के मार्गदर्शन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा श्री विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित की गई। परीक्षा सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चली। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा इस महापरीक्षा में 24,414 परीक्षार्थियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सायं 4:00 बजे तक 16,258 नवसाक्षर परीक्षार्थी उपस्थित हुए। जिलेभर में परीक्षा को महोत्सव जैसा माहौल मिला, गांवों

में शिक्षार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। कई परीक्षा केन्द्रों में एक ही परिवार से सास-बहू, पति-पत्नी, देवगानी-जेठानी समेत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए। कई महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर परीक्षा दी, जो उनके शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में भी बना परीक्षा केन्द्र - वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी वाणी मुखर्जी ने बताया कि केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में भी परीक्षा केन्द्र स्थापित किया गया था, जहाँ 219 नवसाक्षर बंदियों ने उत्साहपूर्वक परीक्षा दी। केन्द्र की व्यवस्था का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा, अपर कलेक्टर अमृत लाल धुव, सहायक संचालक अनिल अग्रवाल, गिरीश गुप्ता, एम. सिद्धिकी (निदेशक जन शिक्षा संस्थान) सहित कई



अधिकारियों द्वारा किया गया। जेलर कलाम, केन्द्राध्यक्ष तिरदा टोपी एवं पर्यवेक्षक दिगम्बर सिंह का विशेष सहयोग रहा। **466 परीक्षा केन्द्रों में उत्साह के साथ आयोजित परीक्षा** : जिले में कुल 466 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे, जिनमें दोपहर 4 बजे तक 14,648 शिक्षार्थियों ने परीक्षा दी। विकासखंड स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अभिलाषा खरे द्वारा की गई और समय-समय पर रिपोर्ट राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को भेजी गई। जिले में आयोजित यह महापरीक्षा न केवल साक्षरता बढ़ने का प्रयास है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कदम भी है। बड़ी संख्या में नवसाक्षर, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और जेल बंदियों की सहभागिता इस अभियान की सफलता और प्रभाव का प्रमाण है।

विद्युत विभाग की बकायादारों पर बड़ा कार्यवाही 23 बकायादारों के काटे गये कनेक्शन

-संवाददाता-

सूरजपुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

विगत दिवस 05 दिसम्बर 2025 को सूरजपुर उपसंभाग अंतर्गत वितरण केंद्र सूरजपुर शहर एवं ग्रामीण में विशेष वसूली अभियान चलाया गया, जिसके तहत विभागीय टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य अभियंता अम्बिकापुर क्षेत्र श्री यशवंत शिलेदार एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री आवेदन कुजुर के निर्देशन में, कार्यपालन अभियंता बसंत सोम तथा जिले में पदस्थ सहायक एवं कनिष्ठ अभियंतों की संयुक्त टीम ने सुबह बकायादारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। इस दौरान 38 बकायादारों के कनेक्शनों में बकाया राशि 16,05,777 रुपये की सूची संयुक्त टीम को वसूली हेतु दी गई। उनके द्वारा संघन लाइन विच्छेदन/बकाया राशि भुगतान की कार्यवाही में 23 बकायादारों के विरुद्ध 8,37,494 ₹ के कनेक्शन काटे गए एवं 15 बकायादारों ने तत्काल अपने बकाये



का भुगतान करते हुए कुल 2,85,380 रुपये जमा किए। मुख्य अभियंता शिलेदार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बकाया वसूली के लिए प्रतिदिन इसी प्रकार सघन मुहिम चलाएं, ताकि बकाया राशि की रिकवरी में तेजी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं, उनके घरों में शाम के समय नियमित जांच की जाए। यदि कोई उपभोक्ता बिजली का उपयोग अनाधिकृत रूप से करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजपुर पुलिस के द्वारा साइबर अपराध एवं नशा मुक्ति को लेकर साप्ताहिक बाजार में आयोजन कर लोगों को दी जानकारी

-संवाददाता-

राजपुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

इक्कीसवीं सदी के दौर में डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगों से लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। आम जनमानस ठगी का शिकार ना हो एवं नशे से होने वाले दुष्परिणाम को रोकथाम के लिए राजपुर पुलिस के द्वारा राजपुर

में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में जागरूकता के तहत आयोजन कर नए कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर आयोजित कर बाजार आए आमजनों को पुलिस टीम ने साइबर ठगों से कैसे बचें उसकी जानकारी दी साथ ही नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताते हुए कल नसा व्यक्ति के

विनाश का कारण है जिससे कई परिवारों का घर उजड़ गया है कई अपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं इससे दूर रहने की सलाह दी। ध्यान आकर्षित करने के लिए बाजार में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया गया था। साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर आकर्षित किया गया नागरिकों को विभिन्न विषयों पर सरल और

महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह के निर्देशन में पुलिस कर्मियों ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 'साइबर फ्रॉड आज हर ओ आमजनता जो मोबाइल चलाता है उसके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। साइबर ठगों द्वारा आय दिन नए नए तरीके अपनाकर प्रलोभन देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है।

भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी होंडा की ये दमदार एसयूवी...जल्द हो सकती लांच

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर 2025। वाहन निर्माता होंडा की ओर से भारतीय बाजार में सेडान से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की विविधता बढ़ती है। निर्माता की ओर से जल्द ही अपने पोर्टफोलियो में नई कारों को जोड़ने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा डब्ल्यूआर-वी आरएस को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा की नई एसयूवी को पूर्ण में एआरआई के पास देखा गया है।



इस दौरान एसयूवी को किसी भी तरह से देखा नहीं गया था। जिससे यह उम्मीद है कि इस एसयूवी को भारत में लांच किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट को इंडोनेशिया से लाया गया है क्यों कि इस पर

लगी प्लेट पर होंडा जकार्ता सेंटर लिखा था। साथ ही विंडशील्ड पर एक कागज लगाया गया था, जिस पर टेस्टिंग व्हीकल लिखा हुआ था। होंडा की ओर से इंडोनेशिया में ऑफर की जाने वाली डब्ल्यूआर-वी आरएस में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में एलईडी लाइट, आरएस एयरो किट, 17 इंच अलॉय व्हील्स, ब्लैक इंटीरियर, सात इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4.2 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेनचेंज कैमरा, एयरबैग, क्रूज कंट्रोल, होंडा सेंसिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं निर्माता की ओर से इस एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है।

बीते सप्ताह शीर्ष पांच कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 72,285 करोड़ बढ़ा

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर 2025। पिछले सप्ताह भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में पांच का कुल बाजार मूल्यांकन 72,284.74 करोड़ बढ़ गया। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस को सबसे अधिक लाभ हुआ। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो और एलआईसी के बाजार मूल्यांकन में गिरावट रही। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 35,909.52 करोड़ रुपए बढ़कर 11,71,862.37 करोड़ रुपए हो गया। इन्फोसिस का मूल्यांकन 23,404.55 करोड़ रुपए बढ़कर 6,71,366.53 करोड़ रुपए पहुंचा। बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण



6,720.28 करोड़ रुपए बढ़कर 6,52,396.39 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल का 3,791.9 करोड़ रुपए बढ़कर 12,01,832.74 करोड़ रुपए हो गया।

इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का भी बाजार मूल्यांकन बढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 35,116.76 करोड़ रुपए घटकर 20,85,218.71 करोड़ रुपए रह

गया, बावजूद इसके वह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो और एलआईसी में भी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स महज 5.7 अंक बढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 16.5 अंक गिरा। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत कंपनियों के शेयरों में महत्वपूर्ण बदलाव के बावजूद मुख्य सूचकांक में ज्यादा हलचल नहीं रही। विश्लेषकों के अनुसार आईटी कंपनियों टीसीएस और इन्फोसिस में निवेशक विश्वास मजबूत बना हुआ है, जबकि रिफाइनरी और वॉकिंग क्षेत्रों में कुछ दबाव के चलते गिरावट रही।

नीलकण्ठधाम

जहाँ प्रकृति और अध्यात्म एक साथ संगम बनाते हैं



पहाड़ की चोटी पर बसे नीलकण्ठ धाम से दिखता 'हरितीमा का अनंत सागर'
कोरिया-सिंगरौली सीमा का छुपा खजाना: प्रकृति, शांति और अध्यात्म का दुर्लभ मेल
राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं का अनसुआ स्थल...
राज्य सीमांत पर स्थित नीलकण्ठ धाम का विहंगम दृश्य...

-राजन पाण्डेय-

कोरिया सोनहत, 07 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की सीमा पर स्थित सोनहत विकासखंड के ग्राम दसेर की प्रसिद्ध नीलकण्ठ पहाड़ी पर स्थापित नीलकण्ठ धाम इन दिनों अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है, ऊँचाई पर बसे इस धार्मिक स्थल तक पहुँचने पर नीचे फैली घाटियों और चारों दिशाओं में फैली घनी हरितीमा का सागर मन मोह लेता है। दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर न केवल भगवान नीलकण्ठ के दर्शन करते हैं, बल्कि प्रकृति के इस दुर्लभ संगम का आनंद भी लेते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ की प्रार्थना से



मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भारत की सीमा के नजदीक है और इसके आसपास कई ऐसी ही प्राकृतिक जगहें मौजूद हैं, जिन्हें संवारकर बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

नीलकण्ठ धाम राज्य सीमा की ऊँचाई पर बसा चमत्कारी आध्यात्मिक स्थल

छत्तीसगढ़ के कोरिया और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की सीमा पर, सोनहत विकासखंड के ग्राम दसेर में स्थित नीलकण्ठ धाम, पहाड़ की ऊँचाई पर बसा एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पहुँचते ही यात्रियों को लगता है मानो वे बादलों और हरियाली को छू रहे हों, यह धाम नीलकण्ठ पहाड़ी पर स्थित है, और ऊपर से देखने पर चारों दिशाओं में फैला घने जंगलों का हरा महासागर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने स्वयं इस स्थल को अलौकिक आभा से सजाया हो।

श्रद्धा का केंद्र... मनोकामना पूरी करने वाला धाम

दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ की पूजा और प्रार्थना मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, धाम के आसपास का वातावरण पूर्ण रूप से शांत, आध्यात्मिक और ऊर्जावान है यही कारण है कि लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आते हैं।

प्रकृति की गोद में अनसुए पर्यटन स्थल

नीलकण्ठ धाम के आसपास विस्तृत वन क्षेत्र, घाटियाँ, पहाड़ी ढलान और प्राकृतिक दृश्य इसे 'हिंडन नेचर व्यू प्वाइंट' बनाते हैं, भारत डेवियुमेंट्री के कृपा शंकर पांडेय बताते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान सीमा क्षेत्र में कई ऐसी पर्यटन योग्य जगहें हैं, जिन्हें विकसित किया जाए तो यह क्षेत्र राज्य के प्रमुख इको-टूरिज्म सर्किट में शामिल हो सकता है।

इको-टूरिज्म, धार्मिक टूर और ट्रेकिंग... नीलकण्ठ धाम भविष्य का बड़ा पर्यटन हब

- यह क्षेत्र
- आध्यात्मिक पर्यटन
- प्रकृति प्रेमियों
- ट्रेकिंग उत्साहियों
- और पारिवारिक यात्राओं

सभी के लिए आकर्षक बन सकता है, यदि आधारभूत सुविधाओं और प्रचार-प्रसार को बढ़ाया जाए।

पहुँच मार्ग और यात्रा अनुभव

- धाम तक पहुँचने का रास्ता साहसिक यात्रा जैसा अनुभव देता है।
- पहाड़ी रास्तों पर वाहन चढ़ाई के साथ-साथ पैदल यात्रा भी रोमांच बढ़ती है।
- शीर्ष पर पहुँचते ही विरान पहाड़ियों के बीच अचानक खुलते विशाल हरियाली दृश्यों का पैनोरमा यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
- फोटो स्पॉट... ड्रोन ट्यू से और भी अद्भुत
- ड्रोन से देखने पर पहाड़ी शिखर पर बसा छोटा-सा धाम
- और उसके चारों ओर फैली गहरी घाटियाँ...
- सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक बेहतरीन फ्रेम देते हैं।

आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी

घर-घर स्वदेशी अभियान पर समीक्षा बैठक संपन्न



-संवाददाता-

कोरिया बैकूठपुर, 07 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, बैकूठपुर में आत्मनिर्भर भारत, एस.आई.आर., हर घर स्वदेशी-घर-घर स्वदेशी

अभियान एवं संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल से लेकर आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को नई ऊँचाइयों तक ले जा रही है, जब स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी, तब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कार्यक्रम प्रभारियों के नाम

विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान प्रभारी-रविशंकर राजवाड़े	प्रबुद्धजन एवं वरिष्ठ जन सम्पर्क प्रभारी - बसंत राय
निकाय एवं सरकारी प्रतिष्ठान प्रभारी-राजेश सिंह	सामाजिक प्रतिष्ठान प्रभारी - अशोक जायसवाल
बस स्टैंड हेतु स्टॉल प्रभारी-शारदा गुप्ता	मन की बात कार्यक्रम प्रभारी - कपिल जायसवाल
सार्वजनिक गतिविधियाँ प्रभारी-अनिल साहू	पदयात्रा एवं घर-घर संपर्क अभियान प्रभारी-चुन्नी पैकरा

एस.आई.आर. अभियान पर विशेष बल

जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बी.एल.ए.-2 अपने-अपने मतदान केंद्रों में सभी मतदाताओं का गणना पत्रक पूर्ण कर बी.एल.ओ. को जल्द जमा कराने में सहयोग करें, संगठनात्मक समीक्षा व आगामी कार्यक्रम जिला महामंत्री पंकज गुप्ता ने मंडलवार संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी, इसके साथ ही जिलाध्यक्ष तिवारी ने आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम प्रभारियों की घोषणा की।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारी

बैठक में प्रमुख रूप से देवेन्द्र तिवारी, बसंत राय, रविशंकर राजवाड़े, चुन्नी पैकरा, पंकज गुप्ता, कपिल जायसवाल, ईश्वर राजवाड़े, शिवकुमारी सोनपाकर, प्रदीप तिवारी, शारदा गुप्ता, रामकृष्ण शर्मा, तीरथ राजवाड़े, गणेश यादव, जगनारायण साहू, राकेश गुप्ता, अनिल खटिक, मैनेजर राजवाड़े, रामलखन यादव, राजाराम राजवाड़े, संजय चिकनजुरी एवं दिनेश साहू उपस्थित रहे।

जिले में उल्लास महापरीक्षा संपन्न

303 परीक्षा केंद्रों में पंजीकृत 7049 परीक्षार्थियों में 90 प्रतिशत ने दी परीक्षा



15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के परीक्षार्थियों ने देश, समाज हित में साक्षरता का संकल्प दोहराया

-संवाददाता-

कोरिया, 07 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

जिले में शनिवार, 7 दिसंबर को उल्लास महापरीक्षा का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। जिले के 303 परीक्षा केंद्रों में आयोजित इस परीक्षा में पंजीकृत 7049 परीक्षार्थियों में से 90 प्रतिशत ने परीक्षा में शामिल होकर साक्षरता के प्रति अपना संकल्प दृढ़ किया।

परीक्षा केंद्रों में एक दिन पूर्व ही तैयारी पूरी कर ली गई थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रैली निकालकर



फूल गुलदस्ते भेंटकर किया गया। परीक्षा दिवस को सुबह ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधि भी केंद्रों से ही केंद्रों में गतिविधियाँ शुरू हो में पहुँचे और परीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

उल्लास महापरीक्षा के प्रमुख उद्देश्य

- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान-पढ़ना, लिखना और प्रारंभिक गणित का ज्ञान देना।
- महत्वपूर्ण जीवन कौशल-स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल ज्ञान जैसी आवश्यक बातें सिखाना।
- व्यावसायिक कौशल-रोजगारपरक शिक्षा से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- सतत शिक्षा-आजीवन सीखने की संस्कृति विकसित करना।
- आत्मविश्वास व सतत्कारण-असाक्षर नागरिकों को सक्षम बनाकर समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन-2030 तक 100 प्रतिशत साक्षरता की दिशा में ठोस कदम।

परीक्षा में विशेष दृश्य, पति-पत्नी और पूरा परिवार साथ बैठे

कई परीक्षा केंद्रों में प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिले कहीं पति-पत्नी साथ परीक्षा देते नजर आए, कहीं दंपति अपने बच्चों के साथ बैठकर साक्षरता की इस बड़ी मुहिम में शामिल हुए, कुछ केंद्रों में परीक्षार्थियों के लिए स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था की गई थी।

उल्लास महापरीक्षा का उद्देश्य... जन-जन को साक्षर

इस परीक्षा का मूल उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के असाक्षर नागरिकों को पढ़ना, लिखना, गणना और आवश्यक जीवन कौशलों से सशक्त बनाना, ताकि वे समाज में आत्मविश्वास के साथ योगदान दे सकें, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उच्च लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर बनाने का संकल्प शामिल है।

यह कार्यक्रम कैसे काम करता है ?

स्वयंसेवक-आधारित मॉडल इस अभियान का सबसे मजबूत आधार स्वयंसेवक शिक्षक होते हैं, जो अपने गांव, वार्ड और समुदाय में असाक्षर नागरिकों को पढ़ाने के लिए समय देते हैं, ये स्वयंसेवक घर-घर जाकर शिक्षार्थियों की पहचान करते हैं, निःशुल्क साक्षरता कक्षाएँ चलाते हैं, बुनियादी पुस्तिकाएँ और मॉड्यूल के आधार पर पढ़ाई कराते हैं, सामुदायिक सहभागिता ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संस्थानों की भागीदारी से सीखने का माहौल तैयार किया जाता है, लचीला शिक्षण मॉडल परीक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार समय तय होता है यही कारण है कि इसमें गृहिणियों, बुजुर्गों, श्रमिकों और खेतिहर परिवारों की बड़ी भागीदारी देखी जाती है, मूल्यांकन आधारित प्रगति नियमित मूल्यांकन के बाद ही शिक्षार्थियों को महापरीक्षा में शामिल किया जाता है।

कोरिया जिले में साक्षरता मुहिम की नई ऊर्जा

उल्लास महापरीक्षा के सफल आयोजन ने जिले में साक्षरता अभियान को नई गति दी है, परीक्षार्थियों की 90 प्रतिशत उपस्थिति बताती है कि जनभागीदारी अब नीतिगत लक्ष्य से आगे एक आंदोलन का रूप लेने लगी है।



हमाली राशि

किसान की राहत का वादा.. या भ्रष्ट सिस्टम की कमाई का स्थायी जरिया ?

हमाली राशि किसकी...किसान की सुविधा की या प्रबंधकों की कमाई की ?

कागज़ में किसान को राहत, ज़मीन पर किसान से वसूली...कौन ले रहा हमाली का पैसा ?

धान खरीदी का सबसे बड़ा और अनवरत चलने वाला घोटाला...
किसान फिर भी सबसे ज्यादा ठगा!

हमाली मद में सालाना करोड़ों की लूट, समिति प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल...

प्रशासन रोज आंकड़े जारी कर रहा, पर किसान से ली जा रही मजदूरी कौन देखेगा ?

सरकार देती है 30 लाख तक हमाली राशि, किसान फिर भी जेब से मजदूरी क्यों दे रहा ?

किसानों की जेब कट रही, सिस्टम के लोग मोटे हो रहे, हमाली मद का खर्चा खेती के लिए नहीं, पूरा चैनल फायदा में, धान खरीदी का सबसे बड़ा चालू खेल!

दो दशक से जारी 'हमाली बंदरबांट' का सिस्टम

ध्यान देने वाली बात यह है कि धान खरीदी की यही संरचना 2012-13 से लगातार चल रही है, हर वर्ष करोड़ों की हमाली राशि जारी होती है, लेकिन न पंजीकृत हमाल, न निर्धारित भुगतान, न पारदर्शी रसीद, न बकायदा उपस्थिति, न पेमेंट की ऑडिट सिर्फ कागजी भुगतान और बंदरबांट की गारंटी।

राजनीतिक संरक्षण का बड़ा खेल

छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों में पिछले दो पंचवर्षीय से चुनाव ही नहीं हुए, अध्यक्ष मनोनीत होते हैं और योग्यता सिर्फ एक: सत्ताधारी दल के स्थानीय नेतृत्व का चेला होना, कांग्रेस शासन हो या वर्तमान भाजपा दोनों में समिति अध्यक्षों पर किसानों से ज्यादा कर्मचारियों का हित साधने का आरोप है, सूत्र बताते हैं कई समितियों के अध्यक्ष को धान खरीदी शुरू होने से पहले ही 3 से 5 लाख रुपये तक का 'एडवांस' मिल चुका है, इसलिए वे किसानों के हितों की जगह हमाली-भुगतान में शामिल कर्मचारियों का कवच बनकर खड़े हैं, किसान उन्हें शासन का प्रतिनिधि समझते हैं, लेकिन समिति अध्यक्ष किसानों के शोषणकर्ताओं की छल बन चुके हैं।

फर्जी धान खरीदी और अन्य मदों में भी करोड़ों का खेल

हमाली राशि के अलावा समितियों में कागजी धान खरीदी (फर्जी उपार्जन), राइस मिलर्स की मिलीभगत, खाद-यूरिया वितरण अनियमितता, फसल बीमा के नाम पर कटौती, अमानत राशि का गबन, गुणवत्ता दिखाकर अवैध वसूली हर समिति में लाखों नहीं, करोड़ों का झोल-झाल होता है।

वर्तमान वर्ष: फिर वही खेल...

इस वर्ष भी शासन ने लगभग 14 प्रति क्विंटल जारी किए जिसमें 5 रूपए सुरक्षा व भंडारण 9 हमाली लगभग वही मात्रा खरीद होने पर हमाली राशि फिर लगभग 1 करोड़ रुपये से अधिक बनेगी, पर वास्तविक भुगतान? फिर से सिर्फ 30-35 लाख, यानी इस वर्ष भी 70-80 लाख रुपये का संभावित गोलमाल, हमाली के नाम पर हो रही यह संगठित बंदरबांट सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, किसानों के नाम पर चलाया जा रहा एक सिस्टमेटिक 'शोषण मॉडल' है, जब धान खरीदी के असली श्रमिकों तक एक रुपये का भी हिस्सा नहीं पहुँचता और समिति अध्यक्ष-कर्मचारी-टेक्रेडर पूरे खेल का हिस्सा बने रहते हैं, तब यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, किसानों के साथ किया गया धोखा है।

हमाली राशि किसके लिए ? ... कागज़ में किसान के लिए... ज़मीन पर चैनल की कमाई के लिए...

सरकार किसानों की सुविधा के लिए हमाली मद में मोटी राशि देती है, एक औसत समिति में यह रकम 25-30 लाख रूपए तक पहुँच जाती है, लेकिन किसान मजदूरों को अपनी जेब से मजदूरी देता है, जबकि नियम के अनुसार यह भुगतान समिति को करना चाहिए, सरकार द्वारा भेजी गई हमाली राशि किसान तक पहुँचती ही नहीं, यह राशि प्रायः समिति प्रबंधक, धान खरीदी प्रबंधक, अध्यक्ष और इनके बीच के पूरे चैनल में बंट जाती है, किसान को न तो श्रम से राहत मिलती है, न पैसा बचता है, अर्थात् हमाली राशि नाम की सरकारी सहायता किसान को नहीं, बल्कि समितियों में बैठे प्रभावशाली लोगों को ताकत और मोटी कमाई देती है।



-रवि सिंह-

कोरिया/एमसीबी, 07 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

धान खरीदी के मौसम में सरकार बड़े गर्व से दावा करती है कि किसान को एक रुपये की भी अतिरिक्त मजदूरी नहीं देनी चाहिए, इसलिए हमाली राशि बढ़ाई गई है जो प्रसवित है, करोड़ों रूपए समितियों को भेजे जाते हैं और घोषणा की गई कि सरकार किसान की हर चिंता का समाधान कर रही है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है क्या सरकार की भेजी गई यह राशि किसान तक पहुँच भी रही है? जवाब कड़वा है, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है नहीं। हमाली राशि, जो मजदूरों के भुगतान के लिए दी जाती है ताकि किसान पर वित्तीय बोझ न आए, वह आज धान खरीदी प्रणाली का सबसे बड़ा चालू घोटाला बन चुकी है, कागज़ में यह पैसा किसान की राहत है, लेकिन जमीन पर यह पैसा समिति प्रबंधकों, खरीद केंद्र के प्रभारी,

समिति अध्यक्ष और उनके पूरे चैनल की निजी आय बन चुका है, किसान आज भी मजदूरों को अपनी जेब से भुगतान करता है, निर्बल, मजबूर, और पूरी तरह सिस्टम पर निर्भर किसान के पास विकल्प ही क्या है? धान बेचना है, कम से कम नुकसान में बेचना है तो वह मना भी नहीं कर सकता, ज्यादातर समितियों में मजदूरी वसूली खुलेआम, निर्भीक और बिना किसी निगरानी के होती है, यानी सरकार का पैसा और किसान का पैसा दोनों खर्च होते हैं, लेकिन राहत किसी को नहीं मिलती, सिवाय उन लोगों के जो सिस्टम को अपनी जेब के हिस्सा से चलाता जानते हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल- एक समिति में जब लगभग 20-25 लाख रूपए तक की हमाली राशि आती है, तो उसका हिस्सा कौन लेता है? किसके पास जाता है यह पैसा? किस मजदूर को इसका भुगतान मिलता है? प्रशासन हर दिन खरीदी का आंकड़ा बताता है

कठोर सवाल जो प्रशासन को जवाब देने चाहिए

जब सरकार हमाली राशि देती है, तो किसान को मजदूरों को भुगतान क्यों करना पड़ता है ?

हमाली राशि का ऑडिट कौन करता है ?

समिति प्रबंधकों पर कार्रवाई कब होगी ?

किसान को वास्तविक राहत का लाभ कब तक मिलेगा ?

क्योंकि यदि यह स्थिति जारी रही, तो धान खरीदी में सरकार के वादे और कागज़ी सुधार सिर्फ घोषणा बनकर रह जायेंगे, और उनकी कीमत किसान आज भी चुका रहा है...

मजबूत बनाती हैं, यह सवाल सरकार से ज्यादा, अपने आपको जनता का सेवक कहने वाले प्रशासनिक ढांचे से पूछने की जरूरत है जब हमाली किसान की थी, तो मजदूरी किसान से क्यों? और जब पैसा सरकार ने दिया, तो फायदा समिति प्रबंधन को क्यों? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक धान खरीदी के हर मौसम में हमाली राशि देश की सबसे बड़ी ओपन सीक्रेट लूट बनी रहेगी।

हर दिन प्रशासन धान खरीदी के आंकड़े बताता है...पर कौन बताएगा किसान से वसूली गई मजदूरी का हिसाब ?

प्रशासन रोज प्रेस नोट जारी करता है आज इतने किसानों ने धान बेचा, इतनी मात्रा खरीदी गई लेकिन कोई यह जांचने ग्रामीण समितियों तक जमीन पर उतरता ही नहीं कि क्या किसान से अवैध मजदूरी वसूली की जा रही है? क्या हमाली राशि वास्तव में मजदूरों को दी जा रही है? क्या प्रबंधक और अध्यक्ष इस राशि का बंदरबांट कर रहे हैं? किसान के सामने विकल्प दो ही हैं या तो जेब से मजदूरी दे, या अपना धान खरीदी केंद्र में जमा ही न कर पाए, यानी सरकारी घोषणा और जमीनी सच के बीच पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का खाई खड़ी है।

सरकार की मंशा अच्छी, सिस्टम में बैठे लोग इसे लूट का जरिया बना चुके हैं...

सरकार की सोच किसान पर अतिरिक्त खर्च न आए जमीनी अमल किसान से मजदूरी लो और हमाली राशि खुद बांट लो, यदि हमाली राशि का आज तक सबसे बड़ा पीड़ित कोई है, तो वह किसान ही है, और यदि इसका सबसे बड़ा लाभार्थी कोई है, तो वह समिति प्रबंधन का नेटवर्क है।

सरकार देती है, सिस्टम खा जाता है...

हमाली रकम का पूरा खेल उजागर

कागज़ पर किसान के लिए बनी सुविधा, जमीन पर समितियों की निजी कमाई बन चुकी है। मजदूरों को भुगतान किसान के जेब से, जबकि लाखों की हमाली राशि का बंदरबांट प्रबंधन करता है।

हमाली मद में 25-30 लाख की एंट्री, पर किसान को एक रुपया नहीं...कहाँ जाता है यह पैसा ?

एक समिति में लाखों की राशि पहुँचती है लेकिन भुगतान किसान से वसूला जाता है। मजदूर भी उसी का पैसा लेते हैं, और सरकारी राशि समिति प्रबंधक, अध्यक्ष और चैनल में बंट जाती है।

प्रशासन आंकड़े देखता है, जमीनी सच नहीं...

किसान से अवैध मजदूरी वसूली कौन रोक रहा ?

हर दिन खरीदी के नंबर जारी होते हैं, मगर यह कोई नहीं जांचता कि किसान से जबन मजदूरी वसूली जा रही है या नहीं। हमाली राशि के वास्तविक उपयोग पर निगरानी शून्य है।

कोरिया की समितियों में हमाली का महाघोटाला...1 करोड़ की हकीकत...30 लाख का खर्च...बाकी पैसा कहाँ गया...

धान खरीदी सत्र 2024-25 के आधिकारिक आंकड़े खुद बता रहे हैं कि कोरिया जिले में हमाली राशि के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ चुका है जिले के 16 समितियों में पंजीकृत लगभग 25 हजार किसानों से पिछले वर्ष 12 लाख 80 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार समितियों को 6 प्रति क्विंटल-व्यवस्था हेतु 9 प्रति क्विंटल हमाली भुगतान हेतु कुल मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की राशि पिछले सत्र में

कोरिया जिले को हमाली मद में जारी की गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है? कोरिया जिले की समितियों में पंजीकृत हमाल है ही नहीं, ज्यादातर समितियाँ कुछ 4, 6 या अधिकतम 10 मजदूरों को दैनिक मजदूरी (300 रुपये प्रतिदिन) पर काम करवाती हैं, यदि पूरे खरीदी सत्र का वास्तविक खर्च जोड़ें तो लगभग 50-55 दिन खरीदी कार्य सभी समितियों के मजदूर मिलाकर कुल खर्च 30-35 लाख रुपये से अधिक नहीं बनता फिर 70-80 लाख रुपये कहाँ गए? यह

राशि किन-किन के बीच बंटी? किसने अपने हिस्से का कितना 'कमीशन' तय किया? यह प्रश्न अब किसानों में उबाल पैदा कर रहे हैं, इस वर्ष हमाली राशि बढ़ने का प्रस्तावित घोटाले का आकार योग्य होने की संभावना है सूत्रों के अनुसार इस वर्ष शासन स्तर पर हमाली मद का बड़ा हुआ प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है अनुमान लगाया जा रहा है कि हमाली राशि 9 रुपये से बढ़कर 14-15 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकती है व्यवस्था और भंडारण मद भी बढ़ाया जा सकता है

यदि पिछले वर्ष कोरिया में 12.80 लाख क्विंटल खरीदी पर 1 करोड़ से अधिक की राशि जारी हुई थी, तो इस वर्ष बढ़ी हुई दरों पर यह राशि कोरिया जिले में ही 2.5 से 3 करोड़ रुपये के पार जाएगी, और सबसे बड़ा सवाल क्या मजदूरों का भुगतान बढ़ेगा? या सिर्फ घोटाले का आकार बढ़ेगा? जमीनी वास्तविकता कहती है मजदूर अब भी 300 रुपये रोज की 'मनमानी' मजदूरी पर काम कर रहे हैं, यानी राशि बढ़ेगी, पर हमाली नहीं घोटाला बढ़ेगा।

कलेक्टर कोरिया चंदन संजय त्रिपाठी ने स्काउट्स गाइड्स दल का किया सम्मान

19वीं राष्ट्रीय जंबूरी एवं डायमंड जुबली जंबूरी, लखनऊ में कोरिया जिले का रहा शानदार प्रदर्शन

विभिन्न प्रतियोगिताओं में कोरिया/छत्तीसगढ़ दल को मिला प्रदर्शन-ग्रेड	
ए ग्रेड	फिजिकल डिस्प्ले
मार्ब पारट	बी ग्रेड
कैम्प फायर	कैम्प क्राफ्ट
रंगोली	स्टेट गेट
राज्य प्रदर्शनी	फोक डंस
एथनिक शो	फूड प्लाज़ा
पीजेन्ट्स शो	सी ग्रेड
कलर पार्टी	पावनविधि प्रोजेक्ट



-संवाददाता- बैकुंठपुर/कोरिया, 07 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी एवं डायमंड जुबली जंबूरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटे कोरिया जिले के स्काउट्स एवं गाइड्स दल को आज कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया गया। कलेक्टर एवं पदेन संरक्षक, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ कोरिया चंदन दल को आज कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया गया। कलेक्टर एवं पदेन संरक्षक, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ कोरिया चंदन दल को आज कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया गया। कलेक्टर एवं पदेन संरक्षक, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ कोरिया चंदन दल को आज कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया गया।

राय, जिला क्रीडा अधिकारी जितेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला स्काउट आयुक्त स्काउट नागेश्वर साहू, जिला संगठन आयुक्त गाइड आशा एका, जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड निशा खान, सीनियर गाइड विजय कुजूर, प्रियंका राजवाड़े, तथा जंबूरी जिला प्रभारी एवं विकासखंड सचिव शिव प्रताप सिंह शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को जंबूरी स्मृति-चिन्ह भेंट किया। कलेक्टर त्रिपाठी ने प्रतिभागियों मृत्युंजय राजवाड़े, ईशू राजवाड़े, सुशील कुमार, अनुज किंडो, शुभम, संजय सिंह, तथा गाइड्स श्रेया भगत, सोमा यादव, सिमरन कुजूर से संवाद कर उनके अनुभव सुने।

कलेक्टर बोलीं राष्ट्रीय मंच पर आपका अनुशासन और नेतृत्व जिले का गौरव बढ़ाता है

सम्मान समारोह के दौरान कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभागियों द्वारा दिखाया गया अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और कौशल पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। ऐसे अवसर युवा पीढ़ी को नई दिशा, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना प्रदान करते हैं।

ऐतिहासिक जंबूरी, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, राष्ट्रपति की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ समापन

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित यह जंबूरी 23 से 29 नवम्बर 2025 तक लखनऊ में हुआ। उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री तथा समापन महामहिम राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न होना इसे ऐतिहासिक बनाता है, देश-विदेश से आए 35,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, छत्तीसगढ़ से 366 सदस्यीय दल ने भाग लिया, उनका मार्गदर्शन राज्य मुख्य आयुक्त इन्द्रजीत सिंह खालसा एवं राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू द्वारा किया गया। जिले के प्रतिभागियों ने दिखाया कौशल, कई विधाओं में 'ए ग्रेड' कोरिया जिला दल ने डीएमएफ मद से मिले वित्तीय सहयोग और जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारियों के मार्गदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया।

आवश्यकता है

दैनिक समाचार पत्र में कार्य करने हेतु निम्न पदों के लिए योग्य कर्मठ, जुझारू, महिला/पुरुष की आवश्यकता है।

स.क्र.	पद	संख्या	वेतन
01	सह संपादक	1 पद	15,000
02	समाचार संपादक	1 पद	15,000
03	प्रबंध संपादक	1 पद	15,000
04	शिक्षण प्रभारी	2 पद	10,000 से 15,000
05	न्यूट्रो टीकर	1 पद	10,000 से 15,000
06	संवाददाता	2 पद	8000 से 12,000
07	कार्यालय सहायक	1 पद	7000

नोट:- आवेदक फोन पर संपर्क ना करें। स्वयं बायोडाटा के साथ कार्यालय में संपर्क करें।

पता-कार्यालय दैनिक समाचार पत्र घटती-घटना रानि मंदिर के पास, नमनाकला, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़, मो.नं. - 93401 54656, 98265-32611

धोखा मत दो...ऐसी जिंदगी जीना पसंद करती हैं ऐश्वर्या राय

बताया-क्यों रहती हैं इंटरनेट से दूर?

ऐश्वर्या राय उन सितारों में शुमार हैं जो स्टारडम को खुद पर हावी नहीं होने देती हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या ने मन के मुताबिक काम



किया। मगर वो कौन सी चीज है जिससे वह दूर रहती हैं, हाल ही में एक्स्ट्रेस ने खुलकर अपने जिंदगी के पन्ने खोले हैं। स्टार बन जाने के बाद सितारों से कई तरह की उम्मीदें होती हैं कि वह फलां तरीके की फिल्में करेंगे, इंटरनेट मीडिया पर उनकी मौजूदगी फलां तरीके की होगी। हालांकि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय इन सबसे परे अपनी जिंदगी बिताना पसंद करती हैं। ऐश्वर्या राय न केवल अपने इंटरनेट मीडिया, बल्कि अपनी फिल्मों की पसंद से यह बताना चाहती हैं कि खुद को साबित करने के लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती है। सऊदी अरब के जेद्दा में चल रहे पांचवें रेड सी फेस्टिवल के ओपनिंग समारोह में यह बातें ऐश्वर्या ने अपनी मास्टरक्लास के दौरान कहीं।

संयोग से मिस वर्ल्ड बनीं ऐश्वर्या राय

साल 1994 में विश्व सुंदरी बनी ऐश्वर्या ने कभी इस खिताब को ब्यूटी पैजेंट की तरह नहीं देखा। वह कहती हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतिगोपिता का हिस्सा बनना एक संयोग था। इसे कभी किसी ब्यूटी पैजेंट की तरह नहीं देखा। मैंने इसे एक ऐसे अवसर की तरह देखा, जिसमें मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व कर सकूँ। मैं हैरान थी यह जानकर कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भारतीय लोगों या भारतीय महिला के बारे में कितना कम जानता था। कई लोग तो यह तक सोचते थे कि हम बाघों और सांप की जमीन से आते हैं। मैंने उस खिताब के जरिए हमें विदेश में सही रूप में पेश करने की कोशिश की है।

स्टारडम से इनसिक्योर नहीं हुई ऐश्वर्या

प्रसिद्धि मिलने के बावजूद ऐश्वर्या कभी इनसिक्योर नहीं हुईं। मणि रत्न निर्देशित तमिल फिल्म इरुवर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली ऐश्वर्या इसे लेकर कहती हैं कि असुरक्षा वाली भावनाएं कभी भी मेरे लिए प्रेरक शक्ति नहीं रही हैं। ऐसा कई बार होता है कि आसपास की आवाजें, आपके दिमाग में जाती हैं। उससे आपके फैंसले भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसने मेरे फैंसलों को नहीं बदला। मुझे आज भी याद है कि मणि रत्न (निर्देशक) ने मुझे इरुवर देते हुए कहा था कि यह तुम्हारी कोई लॉन्ग फिल्म नहीं है। यह बस एक फिल्म है, एक कहानी है। मैंने सोचा, वाह, यही वह फिल्म है, जो मैं करना चाहती हूँ। मैंने चोखेर वाली फिल्म भी की थी, वो भी देवदास फिल्म के बाद शिखर पर पहुंचने पर। मैंने यही सोचा था कि खूबसूरत कहानी है, इसलिए करनी चाहिए। मुझे आपका (फिल्म इंडस्ट्री का) प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है। हमारे पास टैलेंट से भरपूर इंडस्ट्री है, जो मुझसे ना सुनने के लिए भी तैयार रहती है, जब मुझे कोई रिस्क पसंद नहीं आती।

इंटरनेट मीडिया से दूर रहती हैं ऐश्वर्या

इंटरनेट मीडिया मान्यता नहीं आगे इंटरनेट मीडिया पर कम समय बिताने को लेकर ऐश्वर्या कहती हैं कि जो इंटरनेट मीडिया पर मुझसे जुड़े हैं, वो जानते हैं कि वहां मेरी मौजूदगी साधारण है। मैंने हमेशा यही सोचा कि उस रास्ते पर नहीं चलने वाली हूँ, जिसकी उम्मीदें यहां मुझसे की जा रही हैं। मैं एक उदाहरण स्थापित करना चाहती थी कि खुद को यह सोचकर धोखा मत दो कि आपको अपने होने का अहसास करने के लिए केवल यही (इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय) करना जरूरी है।

बेटे अभिषेक ने जब ऐश्वर्या राय को किया प्रपोज, अमिताभ बच्चन ने होने वाली बहू से पूछा था ये सवाल

बच्चन परिवार अपनी पर्सनल लाइफ को यूं तो लाइमलाइट से दूर रखता है, लेकिन अमिताभ बच्चन कई मौकों पर परिवार से जुड़ी बातें जरूर शेयर कर देते हैं। ऐसे ही एक बार बिग बी ने बताया था कि जब उनके बेटे अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया था तो उन्होंने होने वाली बहू से क्या सवाल किया था।

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे नामी कलाकारों में से हैं, जो इंडस्ट्री पर 5 दशक से भी ज्यादा समय से राज कर रहे हैं। सुपरस्टार ने 1969 में सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया था और आज भी लगातार काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के अलावा उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या भी फिल्मी दुनिया के सबसे मशहूर सितारे और जोड़ियों में से एक हैं। अभिषेक बच्चन 2007 में ऐश्वर्या राय के साथ शादी के बंधन में बंधे थे और उन दिनों इस बिग फेट वेंडिंग के खूब चर्चे हुए थे। दोनों की शादी को 18 साल हो चुके हैं और दोनों एक बेटी आराध्या के परेंटर हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं जब अभिषेक ने ऐश्वर्या



को प्रपोज किया तो अमिताभ बच्चन ने अभिनेत्री से एक सवाल पूछा था।

अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या से पूछा था ये सवाल

अमिताभ बच्चन ने कुछ साल पहले मिडडे से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें अभिषेक को ऐश्वर्या के प्रस्ताव के बारे में पता चला और कैसे उन्होंने ऐश्वर्या का अपने घर में स्वागत किया। उन्होंने कहा था-मुझे न्यूरॉक से एक फोन आया,

गुरु के प्रीमियर के ठीक बाद। अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और तुरंत मुझे इसके बारे में बताया। अभिषेक और ऐश्वर्या एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा, घर आओ। मैंने ऐश्वर्या से पूछा कि क्या वो खुश है। उन्होंने हां कहा। इसके बाद हम उन्हें घर ले आए और कहा- ये आपका घर है। हमको क्या लेना देना है और कुछ से?

अभिषेक बच्चन,

ऐश्वर्या राय की पहली मुलाकात

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की पहली मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिसे दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में गिना जाता है। अमिताभ बच्चन यहां अपनी फिल्म मृत्युदाता की लोकेशन देखने आए थे और अभिषेक भी उनके साथ मौजूद थे। वहाँ ऐश्वर्या अपनी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो

गया की शूटिंग कर रही थीं। इसी दौरान बाँबी देओल ने अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात कराई थी। लेकिन, तब दोनों के बीच एक फॉर्मल हाय-हेलो ही हुई थी।

गुरु के सेट पर शादी के लिए किया प्रपोज

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने एक-दूसरे को लगभग डेढ़ साल डेट किया और इसके बाद 2007 में गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दोनों के परिवार की तरफ से भी इस रिश्ते को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद ऐश्वर्या और अभिषेक अप्रैल 2007 में शादी के बंधन में बंध गए और शादी के 4 साल बाद नवंबर 2011 में दोनों ने अपनी बेटी आराध्या का इस दुनिया में स्वागत किया। पिछले दिनों दोनों के रिश्ते में दरार की चर्चाएं जोरों पर थीं, लेकिन कपल ने साफ कर दिया कि दोनों अब भी साथ हैं और अब अक्सर दोनों साथ दिखाई देते हैं।

54 की उम्र में सोहेल खान ने किया गजब का ट्रांसफॉर्मेशन

गुड लुक्स में बड़े भइया सलमान खान को भी किया फेल



लुक्स भी पर काम किया है और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन करके सबकी बोलती बंद कर दी है। रविवार को सोहेल खान को आउटिंग के दौरान के स्पॉट किया गया।

सोहेल खान हिंदी सिनेमा के फेमस डायरेक्टर और एक्टर रहे हैं। बीते समय में अपने लुक की वजह से उनको काफी ट्रोल किया गया है। इस बीच एक्टर का लेटेस्ट लुक सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई शॉक हो गया है। 54 साल की उम्र में सोहेल ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है, जिसकी वजह से उनके गुड लुक्स की चर्चा हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर सोहेल खान की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए एक नजर सोहेल की इन फोटोज पर डालते हैं।

बदल गया सोहेल

खान का अंदाज

बीते समय में सोहेल खान को उनके लुक को लेकर भी निशाने पर रखा गया है। आलोचकों ने उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई है। लेकिन अब शायद सोहेल ने अपनी फिटनेस के साथ-साथ लुक्स भी पर काम किया है और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन करके सबकी बोलती बंद कर दी है। रविवार को सोहेल खान को आउटिंग के दौरान के स्पॉट किया गया।

जब तीन हीरो का रोल खा गया था अकेला खलनायक

45 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म आज बनी कल्ट हिंदी फिल्मों के इतिहास में कई ऐसी फिल्में हैं



जो कारोबार के हिसाब से बेहद सफल नहीं हो सकीं, लेकिन कल्ट फिल्म के तौर पर याद की जाती हैं। ऐसी फिल्में अपने क्राफ्ट के कारण वर्षों बाद भी लोगों की जुबान पर होती हैं। जसने भी दो यारो, 'मेरा नाम जोकर' और 'लम्हे' कुछ ऐसी ही फिल्में हैं, जो आज भी बेहतरीन फिल्मों की सूची में शामिल हैं, लेकिन जो सफल फिल्मों की श्रेणी में नहीं आतीं।

शान का शाकाल सब पर भारी

ऐसी ही एक और फिल्म है आज से 45 वर्ष पूर्व

प्रदर्शित हुई 'शान'। फिल्म 'शोले' की सफलता के बाद रमेश सिप्पी एक शहरी और

आधुनिक कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। ऐसी फिल्म जिसमें नायक, नायिकाएं, खलनायक सभी शहरी हों और फिल्म का वातावरण भी आधुनिक लगे। लेखक सलीम-जावेद की हिट जोड़ी उनके साथ थी। फिल्म 'शान' की कहानी तैयार हो गई, जिसमें

इयान फ्लेमिंग के उपन्यासों और जैम्स बांड सीरीज की फिल्मों के खलनायक ब्लोफेल्ड पर आधारित एक खलचरित्र रचा गया। शाकाल नाम का ये पात्र गंजा है।

खेल-समाचार

मुंबई की टीम के लिए खेलेंगे यशस्वी जायसवाल

युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार शतक जड़ा था। जायसवाल की वापसीसे मुंबई की टीम और मजबूत होगी।



बताया, उन्होंने स्मार्ट भियान के लिए खुद को उपलब्ध कराया है। यह खबर मुंबई के फैंस के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जायसवाल की मौजूदगी टीम को और मजबूत बनाएगी। मौजूदा चैंपियन मुंबई, जिसकी कप्तानी शाहुजित लोकर कर रहे हैं, इस समय लखनऊ में हैं और एलाइट ग्रुप ए में टॉप पर

चल रही है। टीम का आखिरी लीग मैच 8 दिसंबर को ओडिशा के खिलाफ है। इंटरनेशनल मैचों के कारण जायसवाल पिछली बार इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने अब तक 28 टी 20 मैचों में 27 के औसत और 136.42 के स्ट्राइक रेट से 648 रन बनाए हैं।

सुपर लीग और श्रेड्यूल जायसवाल के लिए यह टूर्नामेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय चयन समिति ने उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी पांच मैचों की टी 20आई सीरीज से आमंत्रित किया है। टूर्नामेंट का अगला चरण, सुपर लीग 12, 14

और 16 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा, जिसमें सभी एलाइट ग्रुप टी टॉप दो टीमों हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को होगा। जायसवाल की वापसी उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे मैच में 116 रन की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिससे भारत ने सीरीज 2-1 से जीती थी।

रोहित शर्मा पर संशय

हालांकि, रोहित शर्मा के स्मार्ट में खेलने पर अभी भी संशय बना हुआ है। पहले ऐसी खबरें थी कि वह खेल सकते हैं, लेकिन एमसीए रिविwar सुबह तक इस पर कोई पक्की जानकारी का इंतजार कर रहा था। जायसवाल का टीम में शामिल होना मुंबई की टीम की ताकत को बढ़ाएगा और उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगा।

भारतीय टीम टी-20 सीरीज के लिए कटक पहुंची

>> 45 हजार दर्शक देख सकेंगे मैच
>> 9 दिसंबर को साउथ अफ्रीका से मुकाबला



कटक, 07 दिसम्बर 2025। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी-20 मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच को लेकर शहर और स्टेडियम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। करीब 45 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और उनके लिए सुरक्षा व सुविधा के पुरखे इंतजाम किए गए हैं। रविवार को भारतीय टीम कटक पहुंची। दोनों टीमों को भुवनेश्वर एयरपोर्ट से चार बसों के जरिए कटक लाया गया। यहां खिलाड़ियों ने करीब 45 मिनट ग्राउंड पर बिताया और फिर होटल लौट गए।

9 दिसंबर को पहला टी-20 मैच

कटक में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच की टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज को 2-1 से जीता है, जबकि उसे 2 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा है।

अभिषेक एक कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए



नई दिल्ली, 07 दिसम्बर 2025। युवा भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी 20 में एक नया इतिहास रच दिया है। सबसे छोटे फॉर्मेट में खेल रहे अभिषेक ने एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड लिखा है जो कोहली और रोहित जैसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटर्स के लिए भी

मुमकिन नहीं था। सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में आसमान छू लिमिट है, और इस पंजाबी लेफ्ट-हैंडर ने सर्विसेज के खिलाफ 3 छक्के लगाकर एक साल में 100 छक्के लगाने का कारनामा किया है। सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में आईपीएल में हिटिंग करने वाले अभिषेक शर्मा टी 20 में भी अपना

धूम मचाने वाले इस हिटर ने सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में भी शतक बनाया। टी 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 2022 में 68 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 2023 में मशहूर हुए ट्विंमें 67 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। युवा यशस्वी जायसवाल पिछले साल 36 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर थे।



कर्नाटक शहर फरवरी में भारत बनाम नीदरलैंड्स डेविस कप टाई की मेज़बानी करेगा

बेंगलुरु, 07 दिसम्बर 2025। ऑल-इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने घोषणा की कि बेंगलुरु को भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाले डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप स्टेज टाई की मेज़बानी का अधिकार दिया गया है, क्योंकि यह बड़ा इवेंट एक ब्रेक के बाद भारत में वापस आ रहा है। भारत और नीदरलैंड के बीच डेविस कप टाई 7 से 8 फरवरी, 2026 तक बेंगलुरु के एसएम कृष्णा कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु में विश्व स्तरीय टेनिस इवेंट आयोजित करने की एक शानदार विरासत है और यहां टेनिस के प्रति उत्साही प्रशंसक हैं जिन्होंने लगातार इस खेल को सपोर्ट किया है। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारत के प्रमुख टेनिस डेस्टिनेशन में से एक के रूप में बेंगलुरु की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। यह केएसटीएलएल द्वारा हाल ही में बेंगलुरु में बिली जॉन किंग कप प्ले-ऑफ की सफल मेज़बानी के बाद हुआ है, जो पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। इस इवेंट ने शहर की मजबूत बुनियादी ढांचे, कुशल योजना और उत्साही प्रशंसक समर्थन के साथ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने की क्षमता को दिखाया।

इस बार आईपीएल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगे



बेंगलुरु, 07 दिसम्बर 2025। आरसीबी विकट्री पेरुड में भगदड़ की घटना के कारण चिन्नास्वामी स्टेडियम को मैचों के लिए बंद कर दिया गया है। ग्यारह लोगों की मौत के कारण कोर्ट ने आइपीएल मैच भी चिन्नास्वामी से शिफ्ट किए जाएंगे। इस संदर्भ में राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने

अहम टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के लिए गर्व का स्रोत है। उन्होंने कहा कि आईपीएल मैच राज्य में जरूर होंगे। 30,000 क्षमता वाले चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 लाख लोग जमा हो गए थे। इकट्ठा हुई भारी भीड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। जब उन्होंने अंदर भी मैच नहीं हुआ है। खबरें हैं कि आईपीएल मैच भी चिन्नास्वामी से शिफ्ट किए जाएंगे। इस संदर्भ में राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने

छत्तीसगढ़ का स्थिरता का युग...डॉ. रमन सिंह के 15 वर्ष 10 दिन का शासनकाल

न्यूज डेस्क

रायपुर, 07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। 7 दिसंबर 2003 छत्तीसगढ़ राज्य के राजनीतिक इतिहास का वह दिन, जब नए बने राज्य में पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. रमन सिंह ने शपथ ली, और इसी दिन से शुरू हुई वह यात्रा, जिसने अगले 15 वर्ष 10 दिन तक छत्तीसगढ़ की राजनीति, विकास मॉडल और शासन प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया, आज, उनके इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग कार्यकाल को ऐतिहासिक कीर्तिमान के रूप में याद किया जा रहा है एक ऐसा कालखंड जिसमें छत्तीसगढ़ को 'खाद्य सुरक्षा मॉडल', 'स्वास्थ्य बीमा मॉडल', 'ऊर्जा राज्य', और 'सुरासन का प्रयोगशाला' जैसे कई नाम दिलाए।

राज्य गठन के बाद पहली स्थिर सरकार

छत्तीसगढ़ के गठन (2000) के बाद, शुरुआती वर्षों में राज्य की प्रशासनिक संरचना, नीतिगत दिशा और विकास मॉडल को लेकर अनिश्चितता थी, डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य की पहली बार दीर्घ अवधि की स्थिर सरकार मिली, योजनाओं को निरंतरता मिली, और नीतियों का सही रूप में क्रियान्वयन संभव हुआ, यह स्थिरता ही आगे चलकर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत बनी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 'रमन मॉडल' जितने देस को दिया है

डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान बनी छत्तीसगढ़ की निष्पक्ष, पारदर्शी और डिजिटल-ड्राइव पीडीएस प्रणाली, इस सुधार को भारत सरकार, नीति आयोग, कई राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा, मुख्य सुधार में राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण, फर्जी कार्डों का उन्मूलन, जीपीएस आधारित ट्रासपोर्ट सिस्टम, वितरण पर निगरानी, गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न यह मॉडल इतना प्रभावी रहा कि इसे देश भर में आधुनिक पीडीएस मॉडल के रूप में अपनाया गया।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना... विकिर्ता सुरक्षा का राष्ट्रीय आकर...

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, जिसने व्यापक स्तर पर स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, महत्व गरीबों को केशलेस उपचार, निजी और सरकारी दोनों अस्पताल शामिल, 30-40 हजार रुपये तक निःशुल्क इलाज, यह योजना आगे चलकर आयुष्मान भारत की आधार-रचना बनी, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ और कई राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे 'सबसे प्रभावी प्रायोगिक मॉडल' बताया।

ई-गवर्नंस-डिजिटल शासन की शुरुआत

राज्य में सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल मंच पर लाने का कार्य शुरू हुआ, भूमि रिकॉर्ड, पेंशन, रजिस्ट्रेशन और पात्रता योजनाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया।

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कीर्तिमान 15 वर्ष 10 दिन के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह



उद्योग और निवेश...छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक पहचान

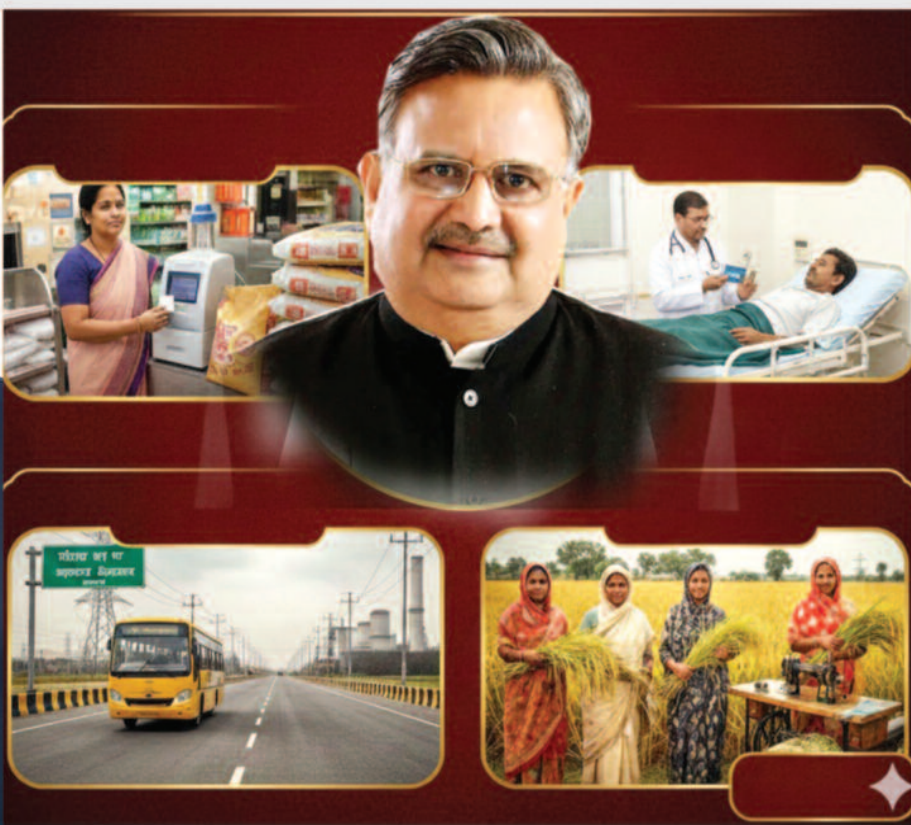
उद्योग, खनिज और ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य ने तेजी से कदम बढ़ाए, स्टील, पावर, सीमेंट और खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार, हजारों करोड़ के निवेश, नीति सुधार के बाद उद्योगिता को बढ़ावा, इसने छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया।

नक्सल क्षेत्रों में सड़क, स्कूल और विकास... एक कठिन लेकिन उल्लेखनीय प्रयास

डॉ. रमन सिंह का सबसे बड़ा प्रशासनिक चैलेंज था, नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर, उनके शासन में पहली बार इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, स्कूलों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा बलों का सुदृढ़ीकरण हुआ, हालांकि चुनौतियाँ बनी रहीं, पर विकास का पहला पहलू बार गति पकड़ सका।

शहरी विकास-नई दिशा

छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वच्छता, पेयजल, सड़कें और यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए, नई नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों का गठन हुआ।



15 वर्ष का सार... एक स्थिर, योजना-बद्ध और प्रबंधन-केन्द्रित शासन

छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह काल सबसे स्थिर शासन, जनकल्याण केन्द्रित योजनाएं, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, प्रशासनिक सुधार का युग माना जाता है, रमन सिंह का 15 वर्ष 10 दिन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक स्वर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है, आज, 7 दिसंबर को उनके इस ऐतिहासिक कीर्तिमान की वर्षा न केवल राजनीतिक हलकों में, बल्कि उन करोड़ों लोगों के बीच भी हो रही है जिन्होंने उनके शासन में बदलाव और स्थिरता का अनुभव किया।

सड़क, विजली और ग्रामीण विकास... छत्तीसगढ़ का बुनियादी ढांचा बदला

15 वर्षों के दौरान राज्य में बड़े स्तर पर, सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, पुल-परियोजनाएँ, पेयजल और सिंचाई संरचनाएँ बनीं, मुख्य उपलब्धियाँ, 18,000+ गांवों तक सड़क संपर्क सिंचाई क्षमता में वृद्धि ऊर्जा उत्पादन में तेजी, गांवों में बिजली आपूर्ति का स्थायित्व छत्तीसगढ़ 'ऊर्जा राज्य' के नाम से पहचाना जाने लगा।

किसान हित... समर्थन मूल्य, बोनास और कृषि सुधार

किसानों के धान का समर्थन मूल्य लगातार बढ़ा, कई वर्षों में प्रति विन्टल बोनास दिया गया, कृषि यंत्रिकरण को बढ़ावा मिला, सिंचाई परियोजनाओं और समितियों की संख्या बढ़ी, धान उत्पादन में छत्तीसगढ़ शीर्ष राज्यों में शामिल हुआ।

महिला व सामाजिक कल्याण

- स्व-सहायता समूहों को मजबूत आधार
- पोषण कार्यक्रमों में सुधार
- बालिका शिक्षा और मातृ-स्वास्थ्य पर फोकस
- योजनाओं में पारदर्शिता लाने का प्रयास

शिक्षा और कौशल विकास

- इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार
- आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ी
- युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र

कार-ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर, 5 की मौत गाड़ी में फंसे शव, जशपुर पुलिस और ग्रामीणों ने मुश्किल से निकाला

जशपुर, 07 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा एनएच-43 पतराटोली के पास हुआ। मनोरा थाना क्षेत्र के मेले से लौट रही आई-20 कार और सामने से आ रहे ट्रेलर के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार सवार सभी 5 युवकों ने मौके पर ही हम तोड़ दिया। कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लोहे के ढेर में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। घटना दुलदुला थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक सभी युवक एक ही गांव के रहने वाले थे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर लौट रहे थे। कार्यक्रम से घर पहुंचने की जल्दी में कार की रफ्तार काफी तेज थी। पतराटोली के पास अचानक सामने ट्रेलर को देखकर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और सभी भीड़ित हो गई। टक्कर होते ही हुआ धमाका : टक्कर होते ही जोरदार धमाका हुआ और कार सड़क किनारे फिसलती चली गई। आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे, लेकिन वाहन के अंदर फंसे सभी युवक मृत पाए



गए। सूचना मिलते ही दुलदुला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस जब पहुंची तो सभी की लाशों कार के अंदर फंसी हुई थी। शवों को वाहन से बाहर निकालने में पुलिस और ग्रामीणों को काफी मशकत करनी पड़ी। बाद में सभी शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला भिजवाया गया, जहाँ पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया की जा रही है। दुलदुला थाना प्रभारी के.के. साहू ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी मृतक दुलदुला थाना क्षेत्र के खटंगा गांव के रहने वाले हैं। पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र : सीएम साय

रायपुर, 07 दिसम्बर 2025। सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र-हर क्षेत्र में सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंच पर सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रारंभ से ही शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य गठन के समय जहाँ मात्र एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में आईआईटी, टिपल-आईटी, आईआईएम, एल्लो यूनिवर्सिटी, एम्स, सिपेट जैसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित



संस्थानों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को बड़े अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाज को मजबूत और संगठित होना समय की आवश्यकता है, क्योंकि संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूलमंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें

मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार 23 महीनों से सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल के महीनों में अनेक महत्वपूर्ण संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूलमंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें

योजना, दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक युक्तियुक्तकरण जैसे कदम शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पर प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई हैं, जिससे युवाओं में नया विश्वास उत्पन्न हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक अवसर, रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे अधिकाधिक संख्या में शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिश्रा ने भी संबोधित किया और नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी।

खूंखार इनामी नक्सल दंपति ने किया सरेंडर

सुकमा, 07 दिसम्बर 2025। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी कड़ी में आज एक और बड़ी सफलता मिली है, जहाँ दरभ डिवीजन के शीर्ष इनामी माओवादी नेता जयलाल उर्फ दिरदो विज्जा और उसकी पत्नी विमला ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। दोनों पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था और ये कई बड़े नक्सली हमलों में वाञ्छित थे। जयलाल उर्फ दिरदो विज्जा पर 25 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह माओवादी संगठन के स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और दरभ डिवीजन इंचार्ज रहा है। मूल रूप से बोडेगुब्बाल, गगनपल्ली पंचायत (थाना फौजबारे, जिला सुकमा) का निवासी जयलाल पिछले 40 वर्षों से संगठन में सक्रिय था और इस दौरान उसने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

सचिव की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट से पंचायत विभाग को मिली फटकार

बिलासपुर, 07 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति में देरी करने पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को फटकार लगाई है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने विभाग के निदेशक प्रियंका थवाईत को कल 8 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। मामला आसिफ राजा की याचिका का है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 22 फरवरी 2024 को रिट अपील में आदेश दिया था कि आसिफ राजा की ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाए।

कांग्रेस ने जलाया भाजपा सरकार का पुतला

किसान की आत्महत्या कोशिश के विरोध में प्रदर्शन, किसान ने टोकन नहीं मिलने पर ब्लेड से काटा गला

रायपुर, 07 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने धान खरीदी में गड़बड़ियों और बागबाहरा के एक किसान द्वारा की गई आत्महत्या की कोशिश के खिलाफ रविवार को उरला में सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में पंकज शर्मा, विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे, शहर अध्यक्ष कुमार मेनन, शिव सिंह ठकुर, विनोद कश्यप, दीपेश सिंह, योगेंद्र सोलंकी, डीगेंद्र सिंह, कृपाराम निषाद, बाबा खान, लखन साहू सहित कई लोग मौजूद थे।



धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार पर लगाए आरोप

भूपेश बघेल ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी, तौल में गड़बड़ी और वजन घटतीली जैसी समस्याएँ आम हो गई हैं। इसके अलावा, धान के लिए की जाने वाली वसूली भी विवाद का कारण बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या किसानों को टोकन को लेकर हो रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में किसान अपने टोकन नहीं कटवा पा रहे हैं और खरीदी की सीमा कम होने से स्थिति और जटिल हो गई है।

नाजुक बनी हुई है। महासमुंद्र जिले के घायल किसान मनबोध गाड़ा से मुलाकात करने शनिवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अंबेडकर अस्पताल पहुंचा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित प्रतिनिधिमंडल ने किसान के परिवार से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने कहा कि किसान सरकार की किसान-विरोधी नीतियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त है और किसान इस व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।

लोन के नाम पर मेडिकल व्यवसायी से 73 लाख ठगो, दिल्ली से चला रहे थे रैकेट

फर्जी सिम-खाते का करते थे इस्तेमाल, 2 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर, 07 दिसम्बर 2025। बिलासपुर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एक मेडिकल व्यवसायी को लोन दिलाने के नाम पर 73 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी फर्जी सिम कार्ड का लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक करके लोगों से ठगी करते थे। बिलासपुर रेंज साइबर थाना ने यह कार्रवाई की। यह मामला सकरी थाना क्षेत्र का है।

आरोपी खुद को अधिकारी बताकर ऑनलाइन ठगी करते थे : पुलिस की पृष्ठभूमि में आरोपियों ने बताया कि वे मुंबई की श्रीराम सिटी यूनिफन फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को काल करते थे। फिर लोगों को कम ब्याज में लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में 28 वर्षीय विकास कुमार उर्फ विक्रम सिंह और अमन कुमार सिंह उर्फ पीयूष शामिल हैं। दोनों बिहार के जिला वैशाली के निवासी हैं। नेचर सिटी सकरी के राजेश पांडेय ने सकरी थाना में ठगी की रिपोर्ट कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें फाइनेंस कंपनी की ओर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी का अफसर बताया और पीएम समृद्धि योजना के तहत 50 लाख रुपये का लोन 30 प्रतिशत छूट में दिलाने की बात कही। इसके लिए उन्हें 12 फरवरी 2024 से 29 सितंबर 2025 के बीच अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कई बार कॉल किया गया। राजेश पांडेय की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिण्टा त्रिवेदी और दूसरे नामों से लगातार किए गए कॉल से वे ठगों के झांसे में आ गए। ठगों ने लोन के लिए राजेश से पहले कुछ अमाउंट जमा करने के लिए कहा।